राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 05 अप्रैल 2026 वर्ष-9,अंक-70 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

केरल में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा, एल डी एफ सरकार की उलटी गिनती शुरू, अब एन डी ए की बारी है

पीएम मोदी ने सबरीमाला रेलवे और महिला सशक्तिकरण के जरिए फूंका जीत का शंखनाद

(एजेंसी)
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवल्ला में चुनावी रैली में भाजपा-एनडीए की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि जनता एलडीएफ-यूडीएफ के कुशासन से बदलाव चाहती है। उन्होंने राज्य सरकार पर सबरीमाला रेलवे जैसी विकास परियोजनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए 'डबल इंजन' सरकार के माध्यम से तीव्र विकास का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल को विश्वास व्यक्त किया कि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद केरलम में भाजपा-एनडीए सरकार का गठन होगा, और उन्होंने राज्य भर में, विशेष रूप से महिलाओं से मिल रहे मजबूत जनसमर्थन पर प्रकाश डाला। केरलम के थिरुवल्ला में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मैं पहले भी यहां आ चुका हूं, लेकिन इस बार बदलाव की हवा अलग दिशा में

बह रही है। केरलम में अब सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 9 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को दशकों के कुशासन का अंत घोषित हो जाएगा। अब यह निश्चित है कि एलडीएफ सरकार के सत्ता से हटने की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। पहली बार केरल में भाजपा-एनडीए की सरकार सत्ता में आ रही है। प्रधानमंत्री ने रैली के रास्ते में देखी गई भारी भीड़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे पहुंचने पर मैंने देखा कि कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले पूरे रास्ते पर भारी भीड़ जमा थी। वामपंथी मानव श्रृंखला की बात करते हैं, लेकिन केरल के लोगों ने एनडीए के प्रति अपना प्रेम मानव दीवार बनाकर दिखाया है। उन्होंने कहा कि नॉर्थईस्ट में एक राज्य को छोड़कर भाजपा-एनडीए की सरकार है और वहां पिछले 50-60 साल में जो काम नहीं हुआ, वो हमने करके दिखाया है। गोवा में लगातार भाजपा-एनडीए की सरकार है, गोवा विकास की नई ऊंचाई को छू रहा है। केरलम में भी एनडीए की सरकार बनेगी तो विकास की नई ऊंचाइयों को पाएंगे। स्थानीय किसानों और मछुआरों की हर समस्या का समाधान हम करेंगे। मोदी ने कहा कि इस चुनाव में केरल को लाभ होगा, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ नुकसान हो सकता है। एनडीए के उम्मीदवार अनूप ने पिछले पांच वर्षों से अटूट समर्पण के साथ मेरे साथ काम किया है। वे एक विश्वसनीय सहयोगी रहे हैं, शांत, ईमानदार और अथक, दिन-रात काम करने वाले। मुझे लगा कि केरल को इस युवा नेता की सेवा और ऊर्जा की आवश्यकता है। आज मैं अनूप को केरल की जनता की सेवा के लिए आपके हवाले करता हूँ। उन्होंने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों ने लंबे समय से इस क्षेत्र की उपेक्षा की है। संपर्क मार्ग जर्जर हालत में हैं। वर्षों से कोई नया पुल नहीं बनाया गया है, और मेडिकल कॉलेज की स्थिति बेहद चिंताजनक है। बुनियादी ढांचे की इस कमी से यह स्पष्ट है कि आपके जीवन स्तर पर कितना गंभीर प्रभाव पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब केंद्र में एलडीएफ और यूडीएफ सत्ता में थे, तब केरल को बहुत कम धनराशि मिलती थी। मोदी सरकार के कार्यकाल में, उस अवधि की तुलना में राज्य को पांच गुना अधिक धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि सबरीमाला रेलवे परियोजना से पूरे क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे और सबरीमाला तीर्थयात्रियों से सीधा संपर्क स्थापित होगा। इससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि, राज्य सरकार ने इस परियोजना में लगातार बाधाएं खड़ी की हैं। केरल में भाजपा की दोहरी इंजन वाली सरकार सत्ता में आते ही ये बाधाएं दूर हो जाएंगी। यह मोदी का आश्वासन है। केरल नई गति से विकास करेगा। इसे भी पढ़ें: बलोचों का ऐलान, अगर हुए आजाद तो भारत को देंगे 3 जबरदस्त चीजें !

मोदी ने कहा कि ठऊअ की नीतियों से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला समूह महिलाएं हैं। महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। हमने उनके जीवन के हर स्तर पर चुनौतियों का समाधान करने के लिए काम किया है। शौचालय निर्माण और बैंक खाते खोलने से लेकर उनके नाम पर घर उपलब्ध कराने और मुद्रा ऋण के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने तक, हमने उनकी नींव मजबूत की है। हम महिला स्वयं सहायता समूहों का भी समर्थन कर रहे हैं, और लखपति दीदी कार्यक्रम ने शानदार परिणाम दिए हैं। हमने पहले ही 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाई हैं, और 3 करोड़ और बनाने का लक्ष्य रखा है। यदि केरल में भाजपा सरकार बनती है, तो महिलाओं को सबसे अधिक लाभ होगा।

FCRA विधेयक पर Kiren Rijiju की कांग्रेस को चेतावनी, झूठ फैलाया तो बेनकाब करेंगे

(एजेंसी)
नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एफसीआरए संशोधन विधेयक का बचाव करते हुए केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है और उन्हें बेनकाब करने की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने ईसाई मिशनरियों से बातचीत की है और यह कानून केवल अवैध विदेशी चंदे वाले खातों को प्रभावित करेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के बारे में फैलाई जा रही झूठ को सरकार बेनकाब करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में ईसाई मिशनरियों से बातचीत की गई है ताकि उनकी चिंताओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जा सके। एएनआई से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि हमने केरल में ईसाई मिशनरियों से बातचीत की है और उनकी चिंताओं को सुना है। हमें सवाल-जवाब और संवाद के माध्यम से मिलकर काम करने की जरूरत है। मंत्री ने दावा किया कि हमने सभी चिंताओं को सुना है और केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का इरादा किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ काम करने का नहीं है। अगर कम्युनिस्ट और कांग्रेस झूठ फैलाना जारी रखते हैं, तो हम उन्हें बेनकाब करेंगे। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि भारत सरकार के तहत अल्पसंख्यकों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और स्पष्ट किया कि प्रस्तावित बदलावों से केवल अवैध एफसीआरए खाते ही प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि मैं अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री हूं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की जाती थी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में निपटा दिए 61 मुकदमे, 32 साल बाद दंपती को मिला तलाक

(एजेंसी)
नई दिल्ली । । भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की एक मिसाल पेश करते हुए तीन दशकों से चल रहे एक लंबे कानूनी संघर्ष का अंत कर दिया है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए एक बुजुर्ग दंपती के बीच चल रहे मामले के साथ कुल 61 मुकदमों को एक झटके में रद्द कर दिया और उन्हें तलाक की मंजूरी दे दी। साल 1994 से चले आ रहे इस विवाद में पति और पत्नी के बीच देश की विभिन्न अदालतों में घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद और मानहानि जैसे दर्जनों मामले लंबित थे। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि जब किसी वैवाहिक रिश्ते में सुधार की कोई गुंजाइश न बचे और वह पूरी तरह टूट चुका हो, तो उसे खींचने के बजाय स्थाई रूप से समाप्त करना ही न्यायसंगत है। यह मामला मूल रूप से अवमानना याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुनवाई के दौरान पीठ ने पाया कि दोनों पक्ष पिछले 30 वर्षों से केवल कानूनी दांव-पेंच में उलझे हुए हैं। कोर्ट ने पहले दोनों पक्षों की काउंसलिंग करवाई और उन्हें आपसी सहमति से अलग होने के लिए प्रेरित किया। लंबी बातचीत के बाद, पति अपनी पत्नी को स्थाई भरण-पोषण (एलिमनी) के रूप में एक करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि देने पर सहमत हुआ।अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में किसी भी पक्ष द्वारा उन्हीं पुराने मुद्दों पर कोई नया केस दर्ज नहीं किया जा सकेगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 का उपयोग पूर्ण न्याय करने के लिए किया गया है ताकि पक्षकारों को कानूनी बाधाओं से मुक्त किया जा सके। दोनों पक्षों ने अदालत के समक्ष सहमति दी कि वे अब कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते है

ए ए पी में हमले झेल रहे राघव चड्ढा का पलटवार- घायल हूं, इसलिए घातक हूं

(एजेंसी)
नई दिल्ली । राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे संसद में शोर मचाने नहीं, बल्कि जनता के मुद्दे उठाने गए थे। उन्होंने इसे एक सुनियोजित हमला बताते हुए कहा कि जल्द ही सारे झूठ बेनकाब हो जाएंगे। राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए गए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने नरम मुद्दों को उठाने के आरोपों के जवाब में अपने बचाव में एक और वीडियो जारी किया है। वीडियो के साथ उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार-बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता। उन्होंने कहा कि कल से मेरे खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चल रहा है। वही भाषा, वही शब्द, वही आरोप। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हमला है। आप नेता ने कहा कि पहले तो मैंने सोचा कि मुझे जवाब नहीं देना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अगर झूठ को सौ बार दोहराया जाए, तो

शायद कुछ लोग उस पर विश्वास कर लें। इसलिए मैंने जवाब देने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी ने तीन आरोप लगाए हैं और कहा है कि इन तीन आरोपों के कारण वे राघव चड्ढा को संसद में बोलने का मौका नहीं देंगे। पहला आरोप यह है कि जब विपक्ष संसद से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं। वे वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरा आरोप यह है कि राघव चड्ढा ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, उन्हें हटाने की याचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह भी एक सरासर झूठ है। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने मुझसे इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा–न औपचारिक रूप से और न ही अनौपचारिक रूप से। और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से छह या सात ने खुद इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो इसमें मेरी क्या गलती है? सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं संसद में शोर मचाने, चिल्लाने, माइक्रोफोन तोड़ने या गाली-गलौज करने नहीं गया था। मैं वहां जनता के मुद्दों को उठाने गया था। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा उन्हें ₹डरपोक₹ कहना गलत है। उन्होंने कहा कि मैं संसद में चिल्लाने, तोड़फोड़ करने या गाली-गलौज करने नहीं गया हूं। मैं वहां लोगों के मुद्दे उठाने गया हूं। पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली के प्रदूषण, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के मासिक धर्म अवकाश तक - मैंने कई मुद्दे उठाए हैं। चड्ढा ने अपने उत्तर का समापन धुरंधर के संदर्भ से कियाः सारे झूठ जल्द ही बेनकाब हो जाएंगे; घायल हूं इसी वजह घातक हूं।

मौसम विभाग ने जारी किया डबल अलर्ट! इन 22 राज्यों में तूफानी बारिश और ओले गिरने की दी चेतावनी

(एजेंसी)
नई दिल्ली । पश्चिमी विक्षोभ के चलते तकरीबन 22 राज्यों में बारिश-ओलावृष्टि का येलो और ऑरेंजे अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली-यूपी में पारा गिरने से गर्मी से राहत मिलेगी। जानिए मौसम का लेटेस्ट अपडेट। अप्रैल की शुरूआत के साथ ही देश के बड़े हिस्से में कुदरत का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग ने एक साथ दो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से अगले कुछ घंटों में देश के 22 राज्यों में भारी उथल-पुथल की चेतावनी जारी की है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान की गलियों तक मौसम ने ऐसी करवट ली है कि कहीं उमस से राहत मिल रही है तो कहीं ओलों की मार से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। यह केवल एक सामान्य बारिश नहीं है, बल्कि तूफानी हवाओं और ओलावृष्टि का वह दौर है जो उत्तर-पश्चिम भारत के तापमान को 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिराने की ताकत रखता है। किसानों की मेहनत पर पानी फेरेंगे ओले इस बदलते मौसम का सबसे दुखद और गंभीर पहलू हमारे देश के मेहनतकश किसानों से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार को अचानक बदले मौसम ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि कर जहां तापमान गिरा दिया, वहीं खेतों में खड़ी फसलों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में तो हालात और भी चिंताजनक हैं, भारी बारिश और ओलों ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभागों में भीषण तूफान और भारी बारिश की चेतावनी दी है। किसानों के मन में अब यह डर बैठ गया है

असम चुनाव: हिमंता का Owais पर तीखा हमला, मिया समुदाय को बना रहे हैं हथियार

(एजेंसी)
नई दिल्ली । असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने असदुद्दीन ओवैसी पर 'मिया समुदाय' को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, साथ ही कांग्रेस पर चुनावी लाभ के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण करने की साजिश में शामिल होने का दावा किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 4 अप्रैल को असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि एआईयूडीएफ के समर्थन में असम दौरे के दौरान उनके चुनावी भाषणों का मकसद राजनीतिक लाभ के लिए मिया समुदाय का इस्तेमाल करना है। उन्होंने कांग्रेस पर ऐसे बयानों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। सरमा ने दावा किया कि कांग्रेस ने चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने और मतदाताओं को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत करने के लिए ओवैसी को असम में भेजा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि

ओवैसी के भाषणों से आबादी के कुछ खास वर्गों को लामबंद करने की कोशिशें झलकती हैं। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ऐसे बयानों की आलोचना करने में विफल रही है और यूनुस तमूली और यूनुस अली जैसे लोगों से जुड़े विवादास्पद बयानों और घटनाओं पर चुप रही है। खोवांग निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा उम्मीदवार चक्रधर गोगोई को भारी जीत मिलेगी, और हाल ही में उनके दौरे के दौरान मिले मजबूत जनसमर्थन का हवाला दिया। सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे पिछले दो वर्षों से जोरहाट के लिए सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हैं।

सोनारी में भाजपा नेता की हत्या के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना को चुनाव से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी, और उचित जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन का रिकॉर्ड और जमीनी स्तर पर पहुंच ने चुनाव से पहले उसकी स्थिति को मजबूत किया है।

केरल में राहुल गांधी का एल डी एफ पर बड़ा हमला, बोले- चुनाव बाद 'वामपंथ' नहीं बचेगा

(एजेंसी)
नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) पर अपनी 'वामपंथी' विचारधारा खोने का गंभीर आरोप लगाया है, और दावा किया कि चुनाव के बाद इसमें कुछ भी वामपंथी नहीं बचेगा क्योंकि सत्ता के लिए उसने भाजपा-आरएसएस से सांठगांठ कर ली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) पर अपनी मूल विचारधारा को त्यागने का आरोप लगाया और कहा कि आगामी चुनावों के बाद एलडीएफ में कुछ भी वामपंथी नहीं बचेगा। 4 अप्रैल को केरल के अलाप्पुझा में एक जनसभा में बोलते हुए गांधी ने एलडीएफ की सिद्धांतों से समझौता करने के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा कि एलडीएफ कई सालों से हमारे विरोधी रहे हैं, हमने

उनसे लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन कई सालों तक वे कुछ ऐसे विचारों के लिए खड़े रहे जिनसे हम सहमत नहीं थे, और हमने उन्हीं विचारों के आधार पर उनका विरोध किया। लेकिन वे किसी बात के लिए खड़े थे, और उसी के प्रतीक के रूप में उनके संगठन के नाम में 'वामपंथी' शब्द है। राहुल ने सवाल किया कि एलडीएफ का मतलब क्या है? वाम लोकतांत्रिक मोर्चा। सच कहूं तो, वाम मोर्चे में कुछ भी 'वामपंथी' नहीं है, और चुनाव के बाद वाम मोर्चे में कुछ भी 'वामपंथी' नहीं बचेगा। गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और वामपंथी दल (एलडीएफ) के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि केरल की सांप्रदायिक सरकार को एक गुप्त शक्ति प्रभावित कर रही है, जो उनके अनुसार संविधान को नकारती है और जनता पर हमला करती है। उन्होंने कहा कि मंच पर बैठे नेता को जो बात परेशान कर रही है, वह यह है कि उनकी नीतियां अब वामपंथी नहीं रहीं। उन्हें और वाम मोर्चे के कई कार्यकताओं को जो बात परेशान कर रही है, वह यह है कि आज एलडीएफ सरकार को एक गुप्त शक्ति चला रही है। यह गुप्त शक्ति सांप्रदायिक है, भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करती, भारत की जनता को बांटती है, उन पर हमला करती है, उन्हें अपमानित करती है, और केरल में हर कोई देख सकता है कि अब भाजपा, आरएसएस और वाम मोर्चे (सीपीएम) के बीच संबंध है। गांधी ने वाम मोर्चे (एलडीएफ) को अवसरवादी नेताओं का समूह बताते हुए कहा कि वे सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और भाजपा एवं आरएसएस से सहायता लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, जो इन विचारों से सहमत नहीं हैं, खुद को धोखा दिया हुआ और आहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वाम मोर्चे के अधिकांश नेता अवसरवादी हैं। यह समझिएः कुछ अवसरवादी नेता सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि भाजपा या आरएसएस उनकी मदद कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं, कुछ नेता किसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। कुछ कार्यकताओं ने विचारधारा के लिए वर्षों तक काम किया है, जो खुद को धोखा दिया हुआ, निराश और आहत महसूस कर रहे हैं और अपनी पार्टी के साथ जो हो रहा है उससे बहुत दुखी हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पश्चिम बंगाल में बढ़ती अराजकता लोकतंत्र के लिए चुनौती

ललित गर्ग

नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है।

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसएआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दशार्ता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसएआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दशार्ता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार पर सीधा हमला है।

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। किंतु यह भी एक चिंताजनक तथ्य है कि इन निदेर्शों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ पार्टी इन निदेर्शों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मयार्दाओं को दरकिनार कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रह जाती, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता का विश्वास होता है, और यदि मतदाता को यह लगने लगे कि मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वतः कमजोर होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक नाकामी का प्रश्न भी गंभीरता से सामने आता है। किसी भी राज्य में यदि अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, न्यायिक अधिकारी तक बंधक बना लिए जाते हैं और पुलिस या प्रशासन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी का स्पष्ट प्रमाण है। प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और सरकारी कार्यों को निर्भय वातावरण में संपन्न कराना होता है। यदि प्रशासन यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो इससे जनता में भय और अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। जनता का विश्वास ही किसी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और जब यही विश्वास डगमगाने लगता है, तो शासन की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक भी होते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यकताओं को संयम, कानून के सम्मान और लोकतांत्रिक मयार्दाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कटु संघर्ष में बदल जाती है और कार्यकताओं को किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल चुनाव को युद्ध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में देखें। आज आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को केवल एक राज्य की समस्या न मानकर लोकतंत्र के लिए चेतावनी के रूप में देखा जाए। यदि प्रशासनिक तंत्र कमजोर होगा, राजनीतिक दल मयार्दा नहीं रखेंगे, और जनता का विश्वास कम होता जाएगा, तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान या न्यायालय नहीं कर सकते, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता और जनता की जागरूकताकृतीनों का संतुलन आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियां हमें यही संदेश देती हैं कि लोकतंत्र को केवल चुनाव से नहीं, बल्कि व्यवस्था की निष्पक्षता, कानून के शासन और नागरिक विश्वास से मजबूत बनाया जा सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और न्यायपालिका मिलकर ठोस कदम उठाएं। कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो और प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मयार्दाओं का पालन करें। निश्चित ही यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह अराजकता और गहराई तक फैल सकती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर कानून, नैतिकता और सहिष्णुता के मूल्यों को पुनः स्थापित करें। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से वह या तो लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ सकता है या अराजकता के गहरे गर्त में गिर सकता है। यह निर्णय न केवल राजनीतिक नेतृत्व, बल्कि पूरे समाज को मिलकर लेना होगा।

संपादकीय

बंगाल में अराजकता

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत निर्वाचन नामावलियों के निस्तारण में लगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। इन सात बंधक अधिकारियों में तीन महिलाएं भी शामिल थीं जिन्हें नौ घंटे तक बिना खाना-पानी के रोके रखा गया। स्वाभाविक रूप से इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव व डीजीपी समेत कई उच्च अधिकारियों का कारण बताओ नोटिस भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सात अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। पिछले महीने तक साठ लाख में 47 लाख आपत्तियों का निस्तारण होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संतुष्टि व्यक्त की है। बहरहाल, इसके बावजूद एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसका निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। बहरहाल, मालदा का यह घटनाक्रम कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी अग्निपरीक्षा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत तथा चुनाव आयोग ने राज्य में जंगलराज होने की बात कही है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी निर्वाचन अधिकारियों से मारपीट व घेराव की घटनाएं सामने आई हैं। जाहिर बात है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कुछ लोगों में असंतोष है। मतदाता सूची से नाम कटने वाले लोगों की तल्ख प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। लेकिन यह तंत्र के प्रति बढ़ते अविश्वास का भी प्रतीक है, जिसके चलते ही घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल में इस महीने होने वाले चुनाव से पहले कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब राज्य में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में इस माह की 23 व 29 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में मालदा का घटनाक्रम निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनौती दशार्ने वाला है।

अफगानिस्तान से लेकर भारत तक भूकंप के झटके!

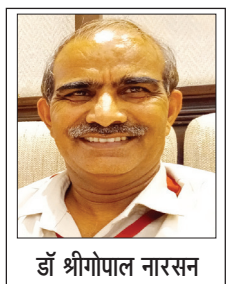

डॉ श्रीगोपाल नारसन

भारत मे दिल्ली-एनसीआर सहित समूचे उत्तर भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके के आने पर लोग घरों से बाहर निकल गए। ये झटके दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा राजस्थानऔर पंजाब सहित कई प्रदेशों में महसूस किए गए हैं। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में बताया जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होने से लोग दहशत में आ गए। गनीमत रही कि भूकंप से कहीं जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई है। भूकंप के झटके जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, पुंछ और कश्मीर घाटी के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र में जमीन के अंदर 175 किलोमीटर नीचे था। भूकंप का केंद्र जमीन के काफी अंदर होने की वजह से इसका असर कम हुआ है। अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सहित उत्तर भारत में भूंकप आने से पहले तिब्बत में धरती हिली थी। तिब्बत में बीती रात करीब 8.12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तिब्बत में आए भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई थी। पिछले साल म्यांमार और थाईलैंड में दोपहर के समय आए भयंकर भूकंप को रिक?टर पैमान पर 7.9 की तीव्रता का नापा गया था। इतने तेज भूकंप के कारण दोनों ही देशों में भारी तबाही हुई थी। इन देशों की विशाल इमारतें और पुल ढह गए और भारी जान माल का नुकसान हुआ था।थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनवात्रा ने बैंकाक के अंदर आपातकाल की घोषणा की थी। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार बताया गया था। जिसका भारी प्रभाव थाईलैंड तक पड़ा था। बैंकॉक में 7.9 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से इमारतें हिलने लगीं थी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जर्मनी के जीएफजेड भूविज्ञान केंद्र ने बताया कि दोपहर को यह भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जिसका केंद्र म्यांमार में था। ग्रेटर बैंकॉक क्षेत्र की आबादी 170 लाख से अधिक है, जिनमें से कई लोग ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट में रहते हैं।दोपहर करीब डेढ़ बजे भूकंप आने पर इमारतों में अलार्म बजने लगे और घनी आबादी वाले मध्य बैंकॉक की ऊंची इमारतों एवं होटल से लोगों को बाहर निकाला गया। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि कुछ ऊंची इमारतों के अंदरूनी हिस्सों में 'स्वीमिंग पूल' में पानी में लहरें उठती दिखीं। भूकंप का केंद्र मध्य म्यांमार में था, जो मोनीवा शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जहां सैंकड़ो लोग इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने बताया कि म्यांमार में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र मंडाले शहर के पास 10 किमी की गहराई पर था। म्यांमार दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड राज्यों में आज आए भूकंप से लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। वही दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्र में विगत वर्ष 17 फरवरी की सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे,जिसमे कई सेकंड तक धरती डोलती रही थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई थी, इसका केंद्र दिल्ली के पास ही धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में था। इसीलिए तेज झटके महसूस हुए। कुछ सेकंड तक चलने वाले भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतों के अंदर जोरदार कंपन महसूस हुआ। भूकंप सुबह 5 बजकर 36 मिनट पर आया था, जिससे लोगों की नींद उड़ गई थी।भूकंप के झटके दिल्ली-एनसीआर भूकंपीय क्षेत्र 4 में आते है, जिससे यहां मध्यम से तीव्र भूकंप आने का खतरा रहता है। समय-समय पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं, लेकिन इस तीव्रता के झटके बहुत समय बाद महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड समेत नेपाल और भारत के अन्य क्षेत्रों में धरती बार बार डोलने लगती है। भूकंप के तेज झटकों से लोग दहशत में आ जाते है। सन 2022 में आए भूकंप के झटके इतने तेज थे कि गहरी नींद में सोए लोग हड़बड़ाहट में उठे और घरों से बाहर की ओर भागे थे।उस समय उत्तराखंड में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई थी। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गुरुग्राम में भी कई सेकेंड तक भीषण झटके महसूस किए गए। इसके कारण लोग उठ गए और कई लोग अपनी सोसायटी में बाहर निकल आए।ऐसा लगा कि बेड को कोई बहुत तेज धक?का मार रहा है। इस दौरान घर के फैन और झूमर भी भूकंप के असर के कारण तेजी से हिलने लगे। भूकंप पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थलमण्डल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकम्पीय तरंगों की वजह से होता है। भूकम्प बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुँचाने से लेकर पूरी आबादी को ध्वस्त

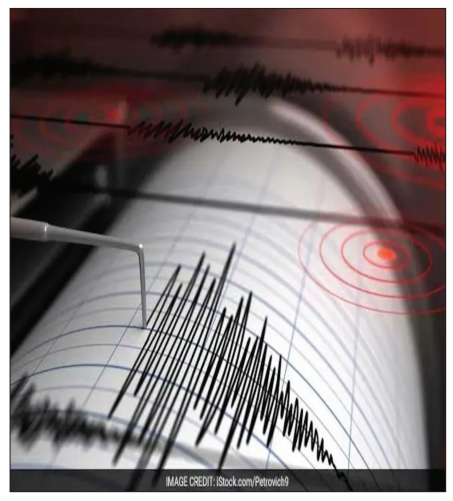

IMAGE CREDIT: iStock.com/Petrovich9

कर सकने की इसमें क्षमता होती है।भूकंप का मापन भूकम्पमापी यंत्र से किया जाता है, जिसे सीस्मोग्राफ कहते है। 3 या उस से कम रिक्टर परिमाण की तीव्रता का भूकंप अक्सर अगोचर होता है, जबकि 7 रिक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति का कारण बन जाता है।भूकंप के झटकों की तीव्रता का मापन मरकैली पैमाने पर किया जाता है।पृथ्वी की सतह पर, भूकंप अपने आप को, भूमि को हिलाकर या विस्थापित कर के प्रकट करता है। जब एक बड़ा भूकंप उपरिकेंद्र अपतटीय स्थिति में होता है, यह समुद्र के किनारे पर पर्याप्त मात्रा में विस्थापन का कारण बनता है। भूकंप के झटके कभी-कभी भूस्खलन और ज्वालामुखी को भी पैदा कर सकते हैं। भूकंप अक्सर भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं।

(लेखक सामाजिक चिंतक व वरिष्ठ साहित्यकार है)

चिंतन-मनन

अपूर्णता से पूर्णता की ओर

मनुष्य का बाह्य जीवन वस्तुतः उसके आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिम्ब मात्र होता है। जैसे ड्राइवर मोटर की दिशा में मनचाहा बदलाव कर सकता है। उसी प्रकार, जीवन के बाहरी ढर्रे में भारी और आश्चर्यकारी परिवर्तन हो सकता है। वाल्मीकि और अंगुलिमाल जैसे भयंकर डाकू क्षण भर में परिवर्तित होकर इतिहास प्रसिद्ध संत बन गये। गणिका और आम्रपाली जैसी वीरांगनाओं को सती-साध्वी का प्रातः स्मरणीय स्वरूप ग्रहण करते देर न लगी। वामित्र और भतृहरि जैसे विलासी राजा उच्च कोटि के योगी बन गये। नृशंस अशोक बौद्ध धर्म का महान प्रचारक बना। तुलसीदास की कामुकता का भक्ति भावना में परिणत हो जाना प्रसिद्ध है। ऐसे असंख्य चरित्र इतिहास में पढ़े जा सकते हैं। छोटी श्रेणी में छोटे-मोटे आश्चर्यजनक परिवर्तन नित्य ही देखने को मिल सकते हैं।

इससे स्पष्ट है कि जीवन का बाहरी ढर्रा जो चिर प्रयत्न से बना हुआ होता है, विचारों में भावनाओं में परिवर्तन आते ही बदल जाता है। मित्र को शत्रु बनते, शत्रु को मित्र रूप में परिणत होते, दुष्ट को संत बनते, संत को दुष्टता पर उतरते, कंजूस को उदार, उदार को कंजूस, विषयी को तपस्वी, तपस्वी को विषयी बनते देर नहीं लगती। आलसी उद्योगी बनते हैं और उद्योगी आलस्यग्रस्त होकर दिन बिताते हैं। दुगरुणियों में सद्गुण बढ़ते और सद्गुणी में दुगरुण उपजते देर नहीं लगती। इसका एकमात्र कारण इतना ही है कि उनकी विचारधारा बदल गई, भावनाओं में परिवर्तन हो गया।

संसार का जो भी भला-बुरा स्वरूप हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, समाज में जो कुछ भी शुभ-अशुभ दिखाई पड़ रहा है, व्यक्ति के जीवन में जो कुछ उत्कृष्ट-निकृष्ट है, उसका मूल कारण उसकी अंतःस्थिति ही होती है। धनी-निर्धन, रोग-नीरोग, अकाल मृत्यु-दीर्घ जीवन, मूर्ख-विद्वान, घृणित-प्रतिष्ठत और सफल-असफल का बाहरी अंतर देखकर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। यह बाहरी भली-बुरी परिस्थितियां मनुष्य के मनोबल, आस्था और अंतःप्रेरणाओं की प्रतीक हैं।

भाग्य यदि कभी कुछ करता होगा तो निश्चय ही उसे पहले मनुष्य की मनोरुचि में ही प्रवेश करना पड़ता होगा, जिसकी अंतःगतिविधियां सही दिशा में चलने लगीं हैं। किंतु जिसका मानसिक स्तर चंचलता, अवसाद, अवास, आलस्य, आवेश, दैन्य आदि से दूषित हो रहा है, उसके लिए अच्छी परिस्थितियां और अच्छे साधन उपलब्ध होने पर भी दुर्गति का ही सामना करना पड़ेगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियमः प्रतिनिधित्व से सशक्तिकरण तक

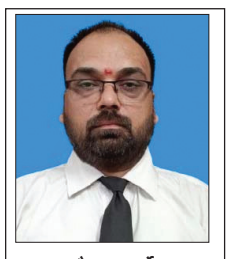

सौरभ वार्ष्णेय

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है, लेकिन राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व लंबे समय तक सीमित रहा। इसी असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से पारित महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) एक ऐतिहासिक पहल के रूप में सामने आया है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है। यह कानून केवल सीटों का आरक्षण नहीं, बल्कि लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब महिलाएं नीति-निर्माण में अधिक संख्या में शामिल होंगी, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अधिक संवेदनशील और प्रभावी निर्णय सामने आ सकते हैं। हालांकि अधिनियम पारित हो चुका है, लेकिन इसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। यानी, इसके वास्तविक प्रभाव को देखने में समय लग सकता है। यह देरी कहीं न कहीं इसकी तत्काल प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

सिर्फ कानून बना देने से ही महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं होता। समाज में पितृसत्तात्मक सोच, राजनीतिक दलों में टिकट वितरण की असमानता, और चुनावी खर्च जैसे मुद्दे अभी भी बाधा बने हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि राजनीतिक दल भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं।यह अधिनियम राजनीतिक दलों की वास्तविक प्रतिबद्धता की भी परीक्षा है। क्या वे महिलाओं को केवल आरक्षित सीटों तक सीमित रखेंगे या सामान्य सीटों पर भी उन्हें पर्याप्त अवसर देंगे? यही इस कानून की सफलता का असली पैमाना होगा।नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। लेकिन इसकी सफलता केवल इसके पारित होने में नहीं, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक मानसिकता में बदलाव पर निर्भर करेगी। यदि इसे सही भावना और नीतियों के साथ लागू किया गया, तो यह भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में महिलाओं की जनसंख्या लगभग आधी है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित बना हुआ है। यह स्थिति केवल आंकड़ों की असमानता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। जब निर्णय लेने वाली संस्थाओं में समाज के आधे हिस्से की भागीदारी कम हो, तो नीतियों में उनकी जरूरतों और दृष्टिकोण का समुचित प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का इतिहास संघर्ष और धीरे-धीरे हुए विस्तार का रहा है। स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण ने निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है, जिससे ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व के नए उदाहरण सामने आए हैं। लेकिन यही प्रगति राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नहीं दिखती। संसद में महिलाओं की संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है, जो यह दशार्ती है कि राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं में महिलाओं को पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा। इस असंतुलन के पीछे कई कारण हैं–सामाजिक रूढ़िवादिता, आर्थिक निर्भरता, शिक्षा और अवसरों की कमी, तथा राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण और धनबल। महिलाएं अक्सर चुनाव लड? के लिए आवश्यक संसाधनों और समर्थन से वंचित रहती हैं। साथ ही, राजनीतिक दल भी उन्हें ₹विनिंग कैंडिडेट₹ के रूप में कम आंकते हैं, जिससे टिकट वितरण में भेदभाव दिखाई देता है।हालांकि, हाल के वर्षों में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा और पहल ने उम्मीद जगाई है। यदि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होता है, तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा, जो न केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा बल्कि नीति-निर्माण में संतुलन भी लाएगा।फिर भी, केवल आरक्षण ही समाधान नहीं है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, और सामाजिक सोच में बदलाव भी उतना ही आवश्यक है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे स्वेच्छा से अधिक संख्या में महिलाओं को टिकट दें और नेतृत्व के अवसर प्रदान करें। साथ ही, समाज को भी महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार करने की मानसिकता विकसित करनी होगी। एक सशक्त लोकतंत्र वही है जिसमें हर वर्ग की आवाज बराबरी से सुनी जाए। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल उनका अधिकार नहीं, बल्कि देश के समग्र विकास और बेहतर शासन की अनिवार्यता है। अब समय आ गया है कि आधी आबादी को आधा प्रतिनिधित्व भी मिले।

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। देश की लगभग आधी आबादी होने के बावजूद संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व सीमित रहा है। ऐसे में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का पारित होना न केवल राजनीतिक सुधार का संकेत है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है। इस बिल के लागू होने को जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया है, जिससे इसकी प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ समय लग सकता है। यही वह बिंदु है, जिस पर विपक्ष और कई विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि यदि सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती है, तो इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी जरूरी है कि आरक्षण केवल संख्या तक सीमित न रहे, बल्कि महिलाओं को वास्तविक नेतृत्व और निर्णय लेने की शक्ति भी मिले। इसके लिए राजनीतिक दलों को अपनी आंतरिक संरचनाओं में भी बदलाव लाने होंगे और महिलाओं को टिकट वितरण में प्राथमिकता देनी होगी। महिला आरक्षण बिल भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह विधेयक केवल महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि यह एक मजबूत, संतुलित और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखने की कोशिश है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

युद्ध के असर से कमो डिटी बाजारों में भारी गिरावट, ऊर्जा संकट ने बढ़ाई चिंता

– एफपीआई बिकवाली और महंगाई के खतरे से निवेशकों में सतर्कता

नई दिल्ली ।

वैश्विक तनाव और ऊर्जा संकट के चलते वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल तेज हो गई है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी से भारत जैसे आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका गहरा गई है। युद्ध के चलते वैश्विक कमोडिटी बाजारों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। मार्च महीने में प्रमुख सूचकांक में दो अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जिसकी बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली रही। कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली तिमाही बाजार के लिए कई वर्षों में सबसे कमजोर साबित हुई है। ऊर्जा कीमतों में उछाल से कंपनियों की लागत बढ़ने की आशंका है, जिससे उनके मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। विशेष रूप से उन सेक्टरों पर असर अधिक दिख सकता है, जो कच्चे माल और ईंधन पर ज्यादा निर्भर हैं। इसके अलावा, होर्मुज स्ट्रेट में बाधा के कारण उर्वरकों की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे आने वाले बुवाई सीजन और खाद्यान्न उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। हालांकि, इस नकारात्मक माहौल के बावजूद ब्रोकरेज हाउस और विश्लेषक पूरी तरह निराश नहीं हैं। उनका मानना है कि मौजूदा संकट अस्थायी है और हालात सामान्य होने पर बाजार में सुधार संभव है। अगले एक साल के लिए बाजार के अनुमानित लक्ष्य में बहुत मामूली कटौती की गई है, जो निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा गिरावट के बीच चुनिंदा सेक्टरों और मजबूत कंपनियों में निवेश के अवसर भी उभर सकते हैं,

खासकर वे जो कमोडिटी कीमतों में बढ़ोतरी से लाभान्वित हो सकती हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार 10.29 अरब डॉलर घटा, 688 अरब डॉलर पर आया

मुंबई।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार चौथे सप्ताह घटकर 688 अरब डॉलर पर आ गया है। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार 27 मार्च को समाप्त सप्ताह में भंडार में 10.29 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई। इससे पहले यह 728.49 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था। विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये में कमजोरी को थामने के लिए बाजार में डॉलर की बिक्री की गई, जिसके चलते भंडार में गिरावट आई। साथ ही गोल्ड रिजर्व में भी कमी दर्ज की गई है। हालांकि अर्थशास्त्रियों के मुताबिक मौजूदा भंडार आयात कवर के लिहाज से अब भी संतोषजनक स्थिति में है।

भारतीय शेयर बाजार में तीन दिन रहा बड़ा उतार-चढ़ाव

- पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान संघर्ष की वजह से निवेशकों का मनोबल कमजोर रहा

मुंबई ।

इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। महावीर जयंती 31 मार्च और गुड फ्राइडे 3 अप्रैल के अवसर पर बाजार बंद रहने के कारण केवल तीन दिन ही कारोबार हुआ। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान संघर्ष की वजह से निवेशकों का मनोबल कमजोर रहा, जबकि सप्ताह के मध्य में सुधार की उम्मीदों ने बाजार को हरा निशान दिखाने में मदद की। विदेशी निवेशकों की निकासी और घरेलू शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत ने सप्ताह की शुरुआत में गिरावट का माहौल बनाया, लेकिन ब्लू-चिप शेयरों में खरीदारी और वैश्विक बाजारों में तेजी से बाजार ने रिकवरी दिखाई। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में ही बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

बीएसई सेंसेक्स 1,191.24 अंक गिरकर 72,391.98 पर आ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 349.45 अंक गिरकर 22,470.15 के स्तर पर था। दिन के अंत में गिरावट और तेज़ हुई और सेंसेक्स 1,635.67 अंक गिरकर 71,947

.55 पर, निफ्टी 488.20 अंक गिरकर 22,331.40 पर बंद हुआ। विदेशी निधियों की निकासी ने इस कमजोरी को और बढ़ाया। बुधवार को बाजार ने मजबूत शुरुआत की। वैश्विक बाजारों में तेजी और अमेरिका-ईरान संघर्ष के जल्द समाधान की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। सेंसेक्स ने शुरुआती कारोबार में 1,899.53 अंक की तेजी दिखाई और 73,847.08 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 572.55 अंक बढ़कर 22,903.95 पर रहा। दिन के अंत में सेंसेक्स 1,186.77 अंक बढ़कर 73,134.32 पर, और निफ्टी 348.00 अंक बढ़कर 22,679.40 पर बंद हुआ। गुरुवार को शुरुआती बिकवाली के बाद दिन के सत्र में बाजार ने रिकवरी दिखाई। सेंसेक्स अपने निचले स्तर से लगभग 950 अंकों की रिकवरी कर पाया और निफ्टी 22,450 का स्तर पार करने में सफल रहा। दोपहर 1 बजकर 43 मिनट पर सेंसेक्स 72,661.06 पर और निफ्टी 22,533.30 पर कारोबार कर रहे थे, जिससे स्पष्ट हुआ कि निवेशक निचले स्तर पर ब्लू-चिप शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ।

पीएनबी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर तबादलों पर पुनर्विचार की मांग की

– अधिकारियों के स्थानांतरण से बैंक के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव का खतरा

नई दिल्ली ।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के वरिष्ठ अधिकारियों के संगठन ने बैंक प्रबंधन से बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों पर पुनर्विचार की मांग की है। संगठन का कहना है कि ऐसे अचानक और व्यापक स्थानांतरण बैंक के संचालन और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अशोक चंद्रा को पत्र लिखकर बताया कि 1,142 स्केल-4 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जो कुल इस स्तर के अधिकारियों का लगभग 25 प्रतिशत हैं। संघ ने आरोप लगाया कि यह कदम नीति का पालन किए बिना मनमाने ढंग से उठाया गया और इसमें महिलाओं को भी राहत नहीं दी गई। संगठन ने प्रबंधन से आग्रह किया है कि वह संतुलित और मानवीय नीति अपनाए, ताकि बैंक की तरक्की और कर्मचारियों का मनोबल बना रहे। पीएनबी में लगभग एक लाख

कर्मचारी हैं, जिनमें स्केल-4 स्तर के करीब 4,000 अधिकारी शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर तबादले बैंक के संचालन और ग्राहक सेवा पर असर डाल सकते हैं।

प्याज का निर्यात 90 फीसदी घटा

-2200 रुपए क्विंटल की प्याज, 800 रुपए क्विंटल पर आई

-बाजार में मांग कम, किसान परेशान

नई दिल्ली ।

देश की प्रमुख प्याज मंडियों में इस समय हालात चिंताजनक बने हुए हैं। निर्यात में करीब 90 फीसदी गिरावट आने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले साल जिस प्याज का भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था, वही अब घटकर करीब 800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिक रही है। मांग में कमी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुस्ती का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ा है।व्यापारियों का कहना है कि विदेशों में ऑर्डर कम मिलने और परिवहन लागत बढ़ने से निर्यात प्रभावित हुआ है। वहीं स्थानीय बाजारों में भी खपत घटने से कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है, जिन्हें लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। कई किसान सरकार से राहत पैकेज और निर्यात प्रोत्साहन की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें आर्थिक संकट से उबारा जा सके।

बीते डेढ़ महीने में सोना 41 हजार और चांदी 1.5 लाख रुपए टूटी

– डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के कारण हो रही गिरावट

मुंबई ।

भारत में बीते डेढ़ महीने में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन बुलियन ज्वैलर्स लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार 29 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोना 1,75,340 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो 2 अप्रैल 2026 को घटकर 1,34,293 रुपए हो गया। इसी अवधि में चांदी की कीमत भी 3,79,888 से घटकर 2,27,813 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। इस तरह केवल डेढ़ महीने में सोने में 41,047 और चांदी में 1,52,075 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। पिछले एक महीने की बात करें तो 2 मार्च 2026 को सोना 1,67,471 और चांदी 2,89,848 रुपए पर थी। तब से अब तक सोने में 33,178 रुपए और चांदी में 62,035 रुपए की कमी आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के कारण हो रही है।

युद्ध जैसी वैश्विक घटनाओं और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश के लिए डॉलर की ओर आकर्षित किया है, जिससे कीमती धातुओं की मांग घट रही है। विश्लेषकों ने

चेतावनी दी है कि सोने और चांदी में निवेश जोखिम से मुक्त नहीं है और कीमतों की अस्थिरता अभी भी जारी रह सकती है।

इसलिए निवेशकों को बाजार की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय रुझानों पर ध्यान देते हुए निवेश करने की सलाह दी जाती है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि में सोना और चांदी फिर से सुरक्षित निवेश विकल्प बन सकते हैं, लेकिन वर्तमान दौर में तेजी से उतार-चढ़ाव के कारण सतर्कता जरूरी है।

ट्रंप के टैरिफ का भारत पर संभा वित असर

नई दिल्ली ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं तथा उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसका भारत पर संभावित असर रहेगा, क्योंकि देश की फार्मा कंपनियों का अमेरिका में बड़ा निर्यात बाजार है। फिलहाल जेनेरिक, बायोसिमिलर और आवश्यक दवाएं टैरिफ से बाहर हैं, जिससे कई कंपनियों की निर्यात गतिविधियां सुरक्षित हैं। हालांकि, पेटेंटेड दवाओं और एपीआई पर बढ़ते टैरिफ से भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और उनका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ घट सकता है। टैरिफ से अमेरिका में उत्पादन और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। लंबे समय में इससे भारत में निवेश, उत्पादन और वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव पड़ सकता है, जबकि अमेरिकी बाजार में भारतीय फार्मा कंपनियों की हिस्सेदारी सीमित होने की संभावना है।

नए हफ्ते आईपीओ बाजार रहेगा सुस्त, केवल 2 नए इश्यू खुलेंगे

मुंबई ।

6 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में प्राइमरी मार्केट में ज्यादा गतिविधि नहीं रहने की संभावना है। इस दौरान केवल दो नए आईपीओ निवेशकों के लिए खुले रहेंगे, जबकि एक पहले से खुला आईपीओ भी जारी रहेगा। वहीं ``` वि विध इलेक्ट्रोमेक के शेयर बाजार में डेब्यू करेंगे। सेफ्टी कंट्रोल एंड` डिवाइस का 48 करोड़ रुपए का आईपीओ 6 अप्रैल से खुलकर 8 अप्रैल को बंद होगा। प्राइस बैंड 75-80 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 1,600 शेयर है।

यह एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होगा और संभावित लिस्टिंग 13 अप्रैल को बीएसई एसएमई पर होगी। प्रोस्फेयर सेलेस्टा का आईपीओ 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक निवेशकों के लिए खुलेगा। कंपनी 244.65 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रख रही है। प्राइस बैंड 10 लाख से 10.5 लाख रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। संभावित लिस्टिंग 24 अप्रैल को बीएसई पर हो सकती है।

27 मार्च को खुला इमाइक टेक्नोलॉजी का आईपीओ 8 अप्रैल तक खुलेगा। इसे अब तक करीब 35 फीसदी सब्सक्रिप्शन मिला है।

वहीं` विविध इलेक्ट्रोमेक के 130.54 करोड़ के शेयर 7 अप्रैल को एनएसई एसएमई पर लिस्ट होंगे, जो पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुके हैं।

वेदांता का मार्च तिमाही में एल्युमिनियम, जिंक का उत्पादन बढ़ा, लौह अयस्क का घटा

– वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही में कंपनी का उत्पादन क्षेत्रवार मिला-जुला रहा

नई दिल्ली।

खनन और ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांता लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही का परिचालन परिणाम जारी कर` दिया है। रिपोर्ट में एल्युमिनियम और जस्ता उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि तेल, लौह अयस्क और इस्पात उत्पादन में गिरावट देखने को मिली। कंपनी के अनुसार मार्च तिमाही में कुल एल्युमिनियम उत्पादन में 2 फीसदी वृद्धि हुई। इसके साथ ही जिंक इंडिया के खनन धातु उत्पादन में भी 2 फीसदी का इजाफा हुआ। यह संकेत है कि धातु खंडों में मांग और परिचालन क्षमता अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। हालांकि, तेल एवं गैस खंड में कंपनी का औसत दैनिक सकल उत्पादन 15 फीसदी घटकर 81,500 बैरल प्रति दिन रह गया। वहीं बिक्री-योग्य लौह अयस्क उत्पादन में 3 फीसदी और इस्पात उत्पादन में 1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी ने बयान में कहा कि वह कुशलता

बढ़ाने, परिचालन पैमाने का विस्तार करने और दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वेदांता का व्यवसाय वैश्विक प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी समूह के तहत खनिज, ऊर्जा संक्रमण धातुएं, तेल एवं गैस और बिजली जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह मिला-जुला प्रदर्शन वैश्विक कच्चे माल की कीमतों, मांग में उतार-चढ़ाव और ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों को दर्शाता है। एल्युमिनियम और जस्ता में वृद्धि कंपनी की कुछ मजबूत धातु लाइन को उजागर करती है

, जबकि तेल, लौह अयस्क और इस्पात में गिरावट उद्योग में अस्थिरता और बाहरी दबाव का संकेत देती है।

इनॉक्सएपी ने होसुर में नया शुद्ध तरल ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया

नई दिल्ली ।

औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल गैस निर्माता इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (इनॉक्सएपी) ने तमिलनाडु के होसुर में नया अति शुद्ध (यूपीएच) तरल ऑक्सीजन प्लांट सफलतापूर्वक चालू किया है। कंपनी का कहना है कि यह कदम देश के उन्नत विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। कंपनी ने बताया कि नया प्लांट विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और सोलर सेल निर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों को समर्थन देगा। इससे उच्च गुणवत्ता वाली तरल ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी और घरेलू विनिर्माण क्षमता मजबूत होगी। इनॉक्सएपी का यह कदम तकनीकी नवाचार और उन्नत विनिर्माण इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे देश में औद्योगिक और मेडिकल गैस के क्षेत्र में मजबूती आएगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आईपीएल 2026: रिजवी ने खेली 90 रन की तूफानी पारी, एमआई को हराकर टॉप पर डीसी

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली, 04 अप्रैल (वेब वार्ता)। दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने शनिवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 8वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की। सीजन की लगातार दूसरी जीत के साथ डीसी ने प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान अपने नाम कर लिया है।

मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने खराब शुरुआत के बावजूद 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए। इस टीम ने तीसरे ओवर में रयान रिकलटन (9) और तिलक वर्मा (0) के विकेट खो दिए थे। उस समय तक टीम के खाते में सिर्फ 18 ही रन जुड़ सके थे। हार्दिक पंड्या के स्थान पर डीसी की कमान संभाल रहे सूर्यकुमार यादव ने यहां से रोहित शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 40 गेंदों में 53 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी।

रोहित 26 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 35 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सूर्या ने 36 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 51 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, नमन धीर ने 28 रन और मिचेल सेंटनर ने नाबाद 18 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी खेमे से मुकेश कुमार ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि लुंगी एनगिडी, अक्षर पटेल, विपराज निगम और टी नटराजन ने एक-एक विकेट हासिल किया।

इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 18.1 ओवरों में जीत हासिल कर ली। मेजबान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। डीसी ने 1.4 ओवरों में महज 7 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से पथुम निसांका ने समीर रिजवी के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 गेंदों में 66 रन जुटाते हुए टीम को 73 के स्कोर तक पहुंचाया।

निसांका 30 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों के साथ 44 रन बनाकर आउट हुए। यहां से रिजवी ने डेविड मिलर के साथ मोर्चा संभाला। दोनों खिलाड़ियों ने चौथे विकेट के लिए 39 गेंदों में 78 रन की साझेदारी करते हुए डीसी को जीत की दहलीज पर ला दिया।

इस बीच, रिजवी अपने आईपीएल करियर का पहला शतक चूक गए। उन्होंने 51 गेंदों में 7 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 90 रन की पारी खेली। मिलर ने नाबाद 21 रन बनाकर टीम को 11 गेंदें शेष रहते जीत दिलाई। विपक्षी खेमे से दीपक चाहर, मिचेल सेंटनर और कॉर्बिन बॉश ने 1-1 विकेट हासिल किया।

आईपीएल 2026: रोहित शर्मा के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि, धोनी का तोड़ा रिकॉर्ड

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2026 के 8वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस की भिड़ंत शनिवार को अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स से हो रही है। मुंबई के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 26 गेंदों में 35 रन बनाए। रोहित ने अपनी इस पारी के दौरान एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

रोहित शर्मा आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके साथ ही वह आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। दिल्ली के खिलाफ 35 रनों की अपनी पारी में रोहित ने एक छक्का लगाया। रोहित दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 51 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने इस मामले में एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है। धोनी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ 50 छक्के लगाए हैं। वहीं, इस लिस्ट में पहले नंबर पर क्रिस गेल का नाम है। गेल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 61 छक्के लगाए हैं।

टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रयान रिकेल्टन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 11 गेंदों का सामना करने के बाद महज 9 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा को मुकेश कुमार ने बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। हालांकि, इसके बाद हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे सूर्यकुमार यादव ने तीसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा के साथ मिलकर 53 रन जोड़े। रोहित 26 गेंदों में 5 चौके और एक छक्के की मदद से 35 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, सूर्यकुमार ने 36 गेंदों में 141 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 51 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए हैं। पूरी तरह से फिट ना होने की वजह से हार्दिक पांड्या यह मुकाबला नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह पर दीपक चाहर को शामिल किया गया है। वहीं, ट्रेंट बोल्ट के स्थान पर कॉर्बिन बॉश और अल्लाह गजनफर की जगह पर मिचेल सैंटनर को टीम में शामिल किया गया है।

स्लो ओवर रेट पर फिर फंसे श्रेयस अय्यर, बीसीसीआई ने जुर्माना किया दोगुना

नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर एक बार फिर स्लो ओवर रेट के कारण चर्चा में हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में शानदार शुरुआत करने वाली पंजाब टीम को इस बार अपने कप्तान की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में पहले ही स्लो ओवर रेट के दोषी पाए जाने के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में भी टीम ने तय समय में ओवर पूरे नहीं किए, जिसके चलते बीसीसीआई ने सख्त कार्रवाई की है। आईपीएल की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह इस सीजन में पंजाब किंग्स का दूसरा उल्लंघन है। ऐसे में श्रेयस अय्यर पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो पिछले मैच में लगे 12 लाख रुपये के जुर्माने से दोगुना है। इसके साथ ही प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर सहित टीम के बाकी खिलाड़ियों पर भी जुर्माना लगाया गया है। खिलाड़ियों को या तो 6 लाख रुपये या उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, भुगतान करना होगा।

हालांकि, बार-बार गलती के बावजूद अय्यर पर किसी तरह के बैन का खतरा फिलहाल नहीं है। आईपीएल में 2025 से पहले तक नियम था कि एक ही सीजन में तीन बार स्लो ओवर रेट के दोषी पाए जाने पर कप्तान को एक मैच का प्रतिबंध झेलना पड़ता था। लेकिन अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत कप्तानों और टीमों पर डिमेरिट पॉइंट्स और जुर्माने का प्रावधान लागू किया गया है। नए नियमों के अनुसार, लेवल-1 के अपराध पर मैच फीस का 25 से 75 प्रतिशत तक जुर्माना और डिमेरिट पॉइंट दिए जाते हैं, जो तीन साल तक रिकॉर्ड में रहते हैं। वहीं गंभीर मामलों में लेवल-2 के तहत चार डिमेरिट पॉइंट दिए जा सकते हैं। हर चार डिमेरिट पॉइंट पर अतिरिक्त जुर्माना या कड़ी सजा दी जा सकती है। हालांकि, सिर्फ स्लो ओवर रेट के आधार पर तत्काल मैच बैन नहीं लगाया जाएगा। इस तरह, पंजाब किंग्स को जीत के बावजूद अनुशासन के मोर्चे पर सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि आगे ऐसे नुकसान से बचा जा सके।

टी20 क्रिकेट में सफल होने सकारात्मक होने के साथ ही गति भी जरुरी : नरेन

कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर लोकप्रिय सुनील नरेन ने कहा है कि टी20 क्रिकेट में सफलता के लिए सकारात्मक रहते हुए निडर होकर खेलना जरुरी है। इसी से वह गति और लय मिलती है जो जीत के लिए सबसे जरुरी है। साथ ही कहा कि खेल में निरंतरता की भी जरुरत रहती है ताकि लगातार प्रदर्शन किया जा सके। साथ ही कहा कि उनकी टीम का भी लक्ष्य जीत हासिल करने का है जिससे लिए वह प्रयासरत हैं हालांकि उसे अभी तक अपने शुरुआती मैचों में सफलता नहीं मिली है। टीम अब अगले मैच में जीत के साथ ही अंक तालिका में अपना

अपना खाता खोलना चाहेगी। उन्होंने कहा कि जब प्रशंसक साथ देते हैं तब भी टीम का हौंसला बढ़ता है। उन्होंने कहा कि आईपीएल में सही समय पर लय हासिल करना, सीनियर खिलाड़ियों का जूनियर खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करना ही सबसे जरूरी होता है।

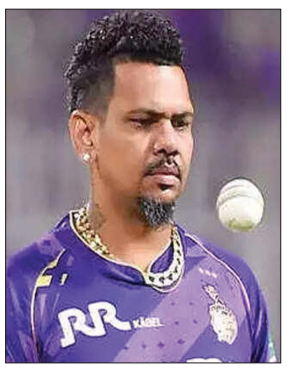

नरेन ने कहा, टी20 क्रिकेट में गति ही सब कुछ होती है। मैच जितनी तेजी से आपके हाथ में आता है उतनी ही तेजी से फिसल भी जाता है। इसलिए सकारात्क बने रहना जरुरी है। इसके साथ ही बिना डरे लगातार अच्छा खेलना होता है। नरेन ने आगे कहा कि लीग में आने वाले युवा खिलाड़ी अब आने वाले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। उन्होंने कहा, आजकल, खिलाड़ी बहुत सारा टी20 क्रिकेट खेलकर लीग में आ रहे हैं। इसलिए यह पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। खिलाड़ी इसमें काफी उत्साहित रहते हैं और वे किसी भी चीज को कम नहीं आंकते। उन्हें पता है कि आईपीलए कितना कठिन है इसलिए वे हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं।

टीम में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए नरेन ने कहा कि वह टीम की जरूरतों के अनुसार खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, खासकर बल्लेबाजी में। उन्होंने कहा, मैं ऐसा खिलाड़ी हूं जो टीम की हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। चाहे पारी की शुरुआत हो या पारी का अंत, मैं वही करता हूं जिसकी टीम को जरूरत होती है।

उद्घाटन समारोह से पहले ही शुरु हो जाएंगे ओलंपिक में फुटबॉल मुकाबले : आईओसी

एथेंस । अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के अनुसार साल 2028 में होने वाले लॉस एंजिलिस ओलंपिक खेलों में फुटबॉल मुकाबले उद्घाटन समारोह से चार दिन पहले ही शुरू हो जाएंगे। आईओसी के अनुसार पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों के मुकाबले 10 जुलाई से शुरु होंगे। ये ये मुकाबले अमेरिका के सात शहरों में होंगे। वहीं ग्रुप स्तर और क्वार्टर फाइनल मुकाबले न्यूयॉर्क, कोलंबस, नैशविले और सेंट लुई में रखे गये हैं जबकि नॉकआउट मुकाबले कैलिफोर्निया के सैन जोस, सैन डिएगो और पासाडेना में आयोजित होंगे। इन शहरों को उपलब्ध विश्वस्तरीय सुविधाएं होने के कारण ही बड़े मुकाबलों के आयोजन का अवसर मिला है। वहीं फुटबॉल का खिताबी मुकाबला ऐतिहासिक रोज़ बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम में ही साल1994 पुरुष फुटबॉल विश्व कप, 1999 महिला विश्व कप और 1984 ओलंपिक का फाइनल भी खेला गया था। आईओसीके नए कार्यक्रम के अनुसार टीमों को पिछले ओलंपिक के मुकाबले आराम के लिए दो दिन और मिलेंगे। इससे खिलाड़ियों को हालातों से उबरने का अच्छा अवसर मिलेगा। फुटबॉल टूर्नामेंट का अंतिम शेड्यूल इस साल के अंत तक जारी किया जाएगा।

आईपीएल 2026 में ऑरेंज-पर्पल कैप की रेस में उलटफेर, पंजाब किंग्स का दबदबा कायम

नई दिल्ली(। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के सातवें मुकाबले के बाद टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की दौड़ में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मुकाबले के बाद दोनों ही कैप पर पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने कब्जा जमा लिया है, जिससे टीम का दबदबा साफ नजर आ रहा है। ऑरेंज कैप की रेस में कूपर कोनोली ने बढ़त बना ली है। उन्होंने चेन्नई के खिलाफ 22 गेंदों में 36 रन की अहम पारी खेलते हुए इस सीजन में कुल 108 रन पूरे कर लिए हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में अंगकृष रघुवंशी 103 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा ईशान किशन (94 रन), हेनरिक क्लासेन (83 रन) और रयान रिकेल्टन (81 रन) भी टॉप बल्लेबाजों में शामिल हैं। पंजाब किंग्स के प्रभसिमरन सिंह ने 43 रन की पारी खेलकर कुल 80 रन के साथ छठे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत की है। वहीं रोहित शर्मा 78 रन के साथ सातवें स्थान पर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 73 रन बनाए और टॉप-10 बल्लेबाजों की सूची में जगह बना ली है। वहीं विराट कोहली और श्रेयस अय्यर भी मध्यक्रम में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

नीलामी में गेंदबाजों को मिस करना पड़ा भारी, फ्लेमिंग

नई दिल्ली । चेन्नई सुपर किंग्स को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में लगातार दूसरी हार के बाद टीम की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। पंजाब किंग्स के खिलाफ 210 रन जैसा बड़ा स्कोर खड़ा करने के बावजूद चेन्नई इसे बचा नहीं सकी। इस हार के बाद टीम के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने माना कि नीलामी के दौरान कुछ अहम गेंदबाजों को टीम में शामिल न कर पाना अब भारी पड़ रहा है। फ्लेमिंग ने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने ऑक्शन के दौरान कई गेंदबाजों पर गंभीरता से विचार किया था, लेकिन परिस्थितियों के चलते वे उन्हें खरीद नहीं सके। उन्होंने स्वीकार किया कि जिन खिलाड़ियों को उस समय नजरअंदाज किया गया, वे अब शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके मुताबिक, टीम ने हर विकल्प पर चर्चा की थी, लेकिन अंत में कुछ खिलाड़ियों को मिस कर दिया गया। चेन्नई की हार ने एक बार फिर गेंदबाजी विभाग की कमजोरियों को उजागर किया है। पंजाब के खिलाफ मैच में बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 209 रन बनाए, लेकिन गेंदबाज विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। इस कारण बड़ा स्कोर भी टीम के काम नहीं आ सका। टी20 क्रिकेट के बदलते स्वरूप पर बात करते हुए फ्लेमिंग ने कहा कि अब पारंपरिक 卐फिनिशर卐 की भूमिका पहले जैसी नहीं रही। उनके अनुसार, आज के खेल में बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हैं और हर ओवर में तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले टीम 16वें ओवर तक पारी संभालती थी, लेकिन अब हर ओवर में 10-12 रन बनाना जरूरी हो गया है। इसके बावजूद फ्लेमिंग ने टीम की बल्लेबाजी पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि चेन्नई के पास डेवाल्ड ब्रेविस जैसे आक्रामक बल्लेबाज और एमएस धोनी जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं। उनके अनुसार, टीम के पास तेज रन बनाने की क्षमता है और बल्लेबाजी में कोई बड़ी चिंता नहीं है। लगातार दो हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पर दबाव बढ़ गया है। अब टीम का अगला मुकाबला रॉयल्स चेलेंजर बेंगलुरुसे है, जहां जीत हासिल कर वापसी करना उसके लिए बेहद जरूरी होगा।

आईपीएल 2026 अर्जुन तेंदुलकर के लिए 'करो या मरो' का मौका, बोले- खेल का मजा लेने पर है फोकस

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 युवा तेज गेंदबाज अर्जुन तेंडुलकर के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंडुलकर के बेटे अर्जुन अब तक आइपीएल में कोई खास पहचान नहीं बना पाए हैं, ऐसे में यह सीजन उनके करियर के लिए निर्णायक माना जा रहा है। वह इस बार लखनऊ सुपर जाइन्टस की ओर से खेलते हुए अपनी छाप छोड़ने के इरादे से उतरेंगे। घरेलू क्रिकेट में मुंबई से गोवा शिफ्ट होने के बाद अर्जुन ने अपनी गेंदबाजी में सुधार दिखाया है और कई मौकों पर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वह अब भी अपने ÷कम्फर्ट जोन÷ से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं। एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान अर्जुन ने कहा कि वह फिलहाल

अपने खेल को एंजॉय कर रहे हैं और उसी पर ध्यान दे रहे हैं।

अर्जुन के करियर में दबाव की बात भी अक्सर उठती रही है, खासकर उनके पिता की विरासत के कारण। इस पर उन्होंने साफ कहा कि वह बाहरी अपेक्षाओं के बजाय अपने खेल पर फोकस करते हैं। उनके मुताबिक, वह क्रिकेट किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जुनून के चलते खेलते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता मेहनत करना और खेल का आनंद लेना है। अर्जुन से जुड़ा एक पुराना किस्सा भी चर्चा में रहा, जब 2016 में कांगा लीग के दौरान एक साथी खिलाड़ी ने उनके पिता के मशहूर 'बूस्ट' विज्ञापन को लेकर मजाक किया था। हालांकि, अर्जुन ने ऐसे अनुभवों को हल्के में लेते हुए हमेशा अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित रखा है।

अब आईपीएल 2026 उनके लिए बड़ा मंच है, जहां अच्छा प्रदर्शन उन्हें नई पहचान दिला सकता है। लगातार मौके मिलने के बावजूद अब तक प्रभाव छोड़ने में असफल रहे अर्जुन के सामने इस बार खुद को साबित करने की चुनौती है। यदि वह इस सीजन में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो न केवल टीम में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं, बल्कि भारतीय क्रिकेट में भी एक मजबूत पहचान बना सकते हैं।

तनाव से बचने क्रिकेट खिलाड़ी गोल्फ भी खेलें : युवराज

नई दिल्ली । पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने क्रिकेटरों को सलाह दी है कि वे मानसिक थकान से राहत पाने के लिए गोल्फ खेलने का भी आनंद लें। युवराज के अनुसार क्रिकेटरों को तनाव से बचने के लिए कम उम्र से ही गोल्फ खेलना चाहिए। युवराज ने कहा है कि उन्होंने संन्यास के बाद गोल्फ खेलना शुरु किया था। युवराज अब दूसरी इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) के ब्रांड एंबेसडर भी हैं। उनका कहना है कि क्रिकेटरों को अपने करियर के दौरान ही गोल्फ भी खेलना भी जारी रखना चाहिये। साथ ही कहा कि मुझे भी पहले ही गोल्फ खेलना शुरू कर देना चाहिए था, इससे मुझे क्रिकेट में भी सहायता मिलती। गोल्फ खेलने का फायदा ये होता है कि शरीर को आराम मिलने के साथ ही तनाव भी कम होता है। युवराज ने कहा, इसी कारण अधिकतर विदेशी क्रिकेटर शुरुआत से ही गोल्फ खेलते आ रहे हैं। युवराज ने कहा कि गोल्फ के बारे में माना जाता है कि ये बड़े लोगों का खेल है जो सही नहीं है। वास्तविकता है कि यह एक ऐसा खेल है जो सभी के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा, हम गोल्फ को एक एलीट खेल के तौर पर देखते हैं पर हमें ये देखना चाहिये कि देश का हर बच्चा गोल्फ खेले। हम गोल्फ को स्कूलों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। मेरा मानना ??है कि हर बच्चे को हर खेल आजमाना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे क्रिकेट हमारे देख में सबसे लोकप्रिय है पर गोल्फ भी एक मजेदार खेल है, जिसे हर किसी को आजमाना चाहिए। भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके एक खिलाड़ी के तौर पर मैं दूसरे खेलों में भी सहायता करना चाहता हूं। गोल्फ लीग इस खेल को और भी रोमांचक बनाएगी और इस खेल को बच्चों की पहुंच में लाने का प्रयास करेगी। हमें उम्मीद है कि ज्यादा बच्चे इस खेल को अपनाएंगे, इसे टीवी पर देखेंगे और इसे खेलने के लिए प्रेरित होंगे।

सऊदी प्रो लीग में चोट से वापसी पर रोनाल्डो ने दो गोल किए

रियाद। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक महीने की चोट के बाद वापसी करते हुए दो गोल किए, जिससे अल-नासर ने सऊदी प्रो लीग में सबसे नीचे चल रही टीम अल-नजमा को हरा दिया। 41 साल के पुर्तगाली फॉरवर्ड ने दूसरे हाफ में दो गोल किए, जिससे इस सीजन में अपने क्लब के लिए उतने ही लीग मैचों में उनके कुल गोलों की संख्या 23 हो गई। रोनाल्डो को फरवरी के आखिर में हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी और पिछले महीने जब पता चला कि चोट शुरू में सोची गई चोट से ज़्यादा गंभीर है, तो वह इलाज के लिए स्पेन चले गए थे। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस पूर्व स्टार ने दो लीग मैच और पुर्तगाल के मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ होने वाले अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडली मैच नहीं खेले। अल-नजमा ने हैरानी भरी बढ़त बना ली, जबकि वह 27 लीग मैचों में सिर्फ़ एक बार ही जीत पाई थी। लेकिन लिवरपूल के पूर्व फॉरवर्ड सादियो माने और अब्दुल्ला अल हमदान ने पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में गोल करके अल-नासर को हाफ-टाइम तक बढ़त दिला दी। मेहमान टीम के बराबरी करने के बाद, रोनाल्डो ने 56वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदलकर अपनी टीम की बढ़त फिर से कायम कर दी; इसके बाद उन्होंने और माने दोनों ने अपना दूसरा गोल करके जीत पक्की कर दी। अल-नासर की लगातार 13वीं लीग जीत ने तालिका में शीर्ष पर उसकी बढ़त को दूसरे स्थान पर काबिज़ अल-हिलाल से छह अंकों तक बढ़ा दिया है; अल-हिलाल शनिवार को अल-तावून के खिलाफ खेलेगा।

इस माह 24 अप्रैल से शुरु होगा थॉमस और उबर कप, लक्ष्य और सिंधु पुरुष और महिला टीम की कमान संभालेंगे

नई दिल्ली । भारतीय बैडमिटंन स्टार लक्ष्य सेन इस माह होने वाले थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष टीम की कमान संभालेंगे। वहीं ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और उभरती खिलाड़ी उन्नति हुड्डा उबर कप में महिला टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय बैडमिंटन संघ ने 24 अप्रैल से तीन मई तक डेनमार्क के होर्सेंस में होने वाले थॉमस और उबर कप के लिए लक्ष्य के अलावा, किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी को टीम में बरकरार रखा है। वहीं युवा आयुष शेट्टी को को भी पहली बार टीम में जगह दी है। पुरुष टीम में एमआर अर्जुन ध्रुव कपिला और किरण जॉर्ज को भी जगह मिली है। वहीं उबर कप में सिंधु, शीर्ष युगल जोड़ी गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली भारती की ओर से पदक की प्रबल दावेदार रहेंगी। भारतीय टीम पिछली बार सेमीफाइनल तक पहुंची थी पर इस बार उसका लक्ष्य और बेहतर प्रदर्शन करना रहेगा। उन्नति हुडा के साथ देविका सिहाग, इशारानी बरुआ और किशोरी तन्वी शर्मा जैसी युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी टीम में रहेंगी। भारतीय बैडमिंटन संघ के अनुसार खिलाड़ियों का चयन 10 मार्च तक की बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग के आधार पर किया गया है, जिसमें शीर्ष पांच एकल खिलाड़ी और शीर्ष दो युगल जोड़ियां शामिल हैं। टीम संयोजन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है।

आईपीएल 2026: सीएसके की गेंदबाजी पर गावस्कर की चिंता, बोले- 230 रन भी नहीं होंगे सुरक्षित

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने चेन्नई सुपर किंग्स की मौजूदा हालत पर चिंता जताते हुए कहा है कि टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गेंदबाजी बनती जा रही है। आईपीएल 2026 में शुरुआती दोनों मुकाबले हारने के बाद सीएसके दबाव में है, जिसमें पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली हार भी शामिल है।

गावस्कर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए साफ है कि सीएसके को अपनी गेंदबाजी पर तुरंत काम करना होगा। उनके मुताबिक, मौजूदा टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजी इतनी मजबूत हो चुकी है कि सिर्फ 200 या 210 रन बनाना काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएसके को मैच जीतने के लिए लगातार 225 से 230 रन के बड़े स्कोर बनाने पड़ सकते हैं, तभी गेंदबाजों को थोड़ा सहारा मिलेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज की टीमों में बल्लेबाजी की गहराई काफी बढ़ गई है। पंजाब किंग्स जैसी टीम में सातवें नंबर पर मार्कस स्टोइनिस जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं, जिससे लक्ष्य का बचाव करना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सीएसके को अपनी गेंदबाजी इकाई को मजबूत करना ही होगा।

इस बीच, युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे की गावस्कर ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि म्हात्रे के लिए बल्लेबाजी क्रम में तीसरा स्थान सबसे उपयुक्त नजर आता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले मैच में पहली ही गेंद पर आउट होने के बावजूद युवा खिलाड़ी ने आत्मविश्वास नहीं खोया और शानदार वापसी की। गावस्कर के अनुसार, नई पीढ़ी के खिलाड़ियों की यही खासियत है कि वे अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गावस्कर ने रोहित शर्मा की फिटनेस में आए बदलाव की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि रोहित ने अपनी शारीरिक स्थिति पर कड़ी मेहनत की है, जिसका असर उनके खेल में साफ दिखाई दे रहा है। उनका फुटवर्क पहले से तेज हुआ है और ऊर्जा भी ज्यादा नजर आ रही है, जिससे वे क्रीज पर ज्यादा समय बिता पा रहे हैं।

वहीं, भारत के एक अन्य अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने पंजाब के युवा खिलाड़ी प्रियांश आर्य की विस्फोटक पारी की सराहना की। पुजारा ने कहा कि प्रियांश गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और खासकर शॉर्ट गेंदों पर आक्रामक शॉट खेलने में माहिर हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसे बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजों के लिए गलती की गुंजाइश बेहद कम रह जाती है। कुल मिलाकर, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स को टूर्नामेंट में वापसी करनी है, तो उसे अपनी गेंदबाजी में जल्द सुधार करना होगा, वरना आगे की राह और मुश्किल हो सकती है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले खिलोने न दें

घर में छोटे बच्चे हो तो हर सदस्य का ध्यान उसकी तरफ ही रहता है। बच्चे के लिए घर में कई तरह के खिलौने भी लाए जाते हैं। उसके लिए साइकिल, वॉकर, छोटे-छोटे खिलौने ला कर रख दिये जाते हैं। कई बार बच्चे के प्यार में जाने-अनजाने अभिभावक कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। आपके घर में भी छोटा बच्चा है। तो इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन से बच्चों के उत्पाद नुकसान पहुंचा रहे हैं।

टीथर

बच्चे रंग-बिरंगे खिलौने देखकर बहुत खुश होते हैं और हर चीज को मुंह में डालते हैं। आप शायद इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि इस खिलौने से बच्चे को संक्रमण होने का डर रहता है। बच्चे को यह खिलौने देने से पहले इस पर धूल मिट्टी के कण पड़े होते हैं। जिसे बहुत से लोग बार-बार साफ नहीं करते और कई बार तो बडे लोगों के हाथ के कीटाणु भी इस पर लग जाते हैं। जिससे बच्चे को उल्टी, पेटदर्द, दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

वाकर

बच्चा जल्दी चलना सीख लें इसलिए ज्यादातर लोग बच्चे को वॉकर लाकर दे देते हैं। माना जाता है कि इसमें बैठकर वह जल्दी चलना सीख जाते हैं और मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। एक शोध में यह बात सामने आई है कि इससे बच्चे को खुद का बैलेंस बनाने में परेशानी होने लगती है। वह डर-डर कर जमीन पर अपने पांव रखता है।

दूध की बोतल

छोटे बच्चे के लिए मां का दूध ही सही आहार है। कुछ कामकाजी औरतें बच्चे बोतल से दूध पिलाती हैं। इससे बच्चे के पेट में हवा भर जाती है, जिससे उसे पेट गैस की परेशानी हो सकती है। अगर बोतल में दूध पिला रहे हैं तो साफ-सफाई का भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। दूध पिलाने से पहले बोतल को जरूर उबाल लें।

बच्चों के लिए बेहद जरूरी है कैल्शियम

कैल्शियम बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। ऐसे में बच्चों के लिए भी ये काफी जरुरी होता है। इसकी कमी से उनके शरीर पर विपरीत प्रभावि पड़ता है। । ये उनकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी कैल्शियम की जरूरत भी बढ़ जाती है। अगर बच्चों को सही मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलता, तो उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

कमी के हैं ये संकेत

कैल्शियम की कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसके कारण बच्चों को चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है और वे दर्द महसूस कर सकते हैं। इससे शिशु को उठने और बैठने में भी मुश्किल हो सकती है ।दांतों की समस्याएं : नवजात शिशुओं में दांतों का देर से आना, दांत कमजोर होना या दांतों में कैविटी की समस्या कैल्शियम की कमी के संकेत होत हैं। मांसपेशियों में दर्द : कैल्शियम की कमी से बच्चों की मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द हो सकता है। यह एक सामान्य लक्षण है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

शारीरिक विकास की धीमी गति : अगर बच्चे की लंबाई और वजन अपेक्षित दर से कम बढ़ रहे हैं, तो यह भी कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से बच्चों की शारीरिक विकास की ट्रैकिंग के लिए सलाह लें।

चिड़चिड़ापन : बच्चों का चिड़चिड़ा होना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करता है, तो यह कैल्शियम की कमी का एक संकेत हो सकता है।

इस प्रकार कमी दूर करे

कैल्शियम युक्त आहार : बच्चों की डाइट में कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। दूध, पनीर, दही और छाछ जैसे खाद्य पदार्थ बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं।

ड्राई फ्रूट्स का सेवन : बच्चों को रोजाना 4 बादाम और 1 अंजीर खिलाएं। इन दोनों में कैल्शियम और विटामिन्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है। हमेशा बादाम और अंजीर को पानी में भिगोकर दें।

विटामिन डी की प्राप्ति : विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। बच्चों को सूरज की रोशनी में बैठने के लिए प्रेरित करें। रोजाना कम से कम आधे घंटे के लिए उन्हें धूप में खेलने का समय दें।

नियमित स्वास्थ्य जांच : कैल्शियम की कमी का पता लगाने के लिए बच्चों की नियमित मेडिकल जांच कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर से सलाह लेकर हर 3 महीने में बच्चे की जांच करवाएं।

लिखना भी एक कला है, लेकिन बच्चों को लिखना सिखाना तो यह और भी बड़ी कला है। बच्चों को लिखना सिखाने के लिए माता-पिता, अध्यापक तथा घर के अन्य बड़े सदस्यों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। बहुत से माता-पिता को यह समस्या होती है कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाया जाए? जिस प्रकार बच्चों को पढ़ाने के लिए लगातार अभ्यास कराना पड़ता है, उसी प्रकार लिखने का भी निरन्तर प्रयास कराना आवश्यक है। पढ़ने की तुलना में लिखना ज्यादा कठिन है। ऐसा देखा गया है कि जो जल्दी पढ़ना सीख जाते हैं वे लिखना देर से सीखते हैं। कुछ बच्चों को पढ़ना-लिखना साथ-साथ सिखाया जाता है। बच्चों को लिखना सिखाने के लिए माता-पिता, अध्यापक तथा घर के अन्य बड़े सदस्यों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है।

यदि बच्चे ने मेहनत करके लिखा है तो बड़ों को चाहिए कि वह उसे देखें तथा उन्हें पढ़ कर सुनाने के लिए कहें। समान्यत : बच्चे वही लिखते हैं, जो सरल पाते हैं। बच्चे लिखने-पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करते। कुछ बच्चे लिखना पढ़ना एक साथ सीख जाते हैं।

बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करें

प्रारम्भ में बच्चों को लिखने की शिक्षा माता-पिता तथा घर के अन्य बड़े सदस्यों द्वारा घर पर ही दी जाती है। बाद में जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो यह जिम्मेदारी शिक्षकों पर आ जाती है, लेकिन स्कूल जाना प्रारम्भ करने के बाद भी माता-पिता की जिम्मेदारी बनी ही रहती है कि बच्चा स्पष्ट व सुंदर लिखे।

शिक्षकों का कहना है कि बच्चों को सर्वप्रथम छपे हुए अलग-अलग वर्णमाला पढ़ना सिखाना चाहिए, जिससे अक्षरों को पढ़ने व पहचानने की क्षमता जागृत हो। आमतौर पर वे बेहद एकाग्र होकर कसकर पैंसिल पकड़ कर लिखते हैं, जिससे उनकी आंखों पर जोर पड़ने की सम्भावना होती है। परिणामस्वरूप शीघ्र ही उसे चश्मा पहनना पड़ता है। माता-पिता को बच्चों की इस आदत पर नियंत्रण प्रारम्भ से ही रखना चाहिए।

आज की पीढ़ी में देखा गया है कि बच्चे काफी कम उम्र में लिखने-पढ़ने के प्रति रुचि दिखाने लगते हैं। विशेषकर दूरदर्शन, रेडियो आदि के प्रभाव से जल्द समझदार हो जाते हैं। उनमें बड़ों को देख कर लिखने की इच्छा जागती है। वे अपना, अपने मित्रों तथा माता-पिता का नाम लिखने का प्रयास करते हैं। माता-पिता या बड़ों को चाहिए कि वे ऐसे मौके का पूरा फायदा उठाएं, बच्चों में सही व सुन्दर लिखने को प्रोत्साहित करें। सीखने की रुचि बच्चों में स्वयं ही होती है। अत : वह बड़ों के कहने को बहुत ही गम्भीरता से लेते हैं, जिससे उनके लिखने की योग्यता विकसित होती है।

बच्चे को जो लिखवाया जा रहा है, उसे जोर-जोर से बोलना चाहिए ताकि वह शब्द बच्चा अच्छी तरह से सुने। बच्चे जैसा सुनेंगे वैसा लिखेंगे। अगर बच्चा अशुद्ध और अस्पष्ट लिख रहा है तो उसे डांटने फटकारने के बजाय प्यार से बताना चाहिए। यदि उसे डांटा-फटकारा गया तो उसमें हीन भावना आ जाएगी और वह यही समझेगा कि मैं सुन्दर और शुद्ध लिख ही नहीं सकता। बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि मैं जो कुछ लिख रहा हूं, उस पर माता-पिता खुश हो रहे हैं। यह बहुत आवश्यक है, इससे बच्चे का उत्साह बढ़ता है। बच्चे किसी एक काम से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, इसलिए लिखने का काम भी उनसे जबरदस्ती नहीं करवाना चाहिए। बच्चे से ऐसी चीजें लिखवाएं जिससे उसमें रुचि पैदा हो।

नाखून चबाने की आदत सेहत के लिए होती है नुकसानदेह

बच्चों को कई बार नाखून चबाने की आदत पड़ जाती है जो उनके स्वास्थ के लिए भी नुकसानदेह होती है। बचपन में इसपर अभिभावक ध्यान नहीं देते पर ये स्वास्थ्य अलावा कई प्रकार के नुकसान का कारण बन सकती है। बच्चों के लिए यह आदत न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हानिकारक हो सकती है। इससे होने वाले नुकसान इस प्रकार हैं।

दांतों और मसूड़े होते हैं खराब

नाखून चबाने से बच्चों के दांतों और मसूड़ों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस आदत से दांतों की संरचना बिगड़ सकती है, जिससे दांतों में असंतुलन, दांतों का टेढ़ा होना या मसूड़ों में सूजन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे बच्चों को दांतों की समस्याएँ बढ़ सकती हैं।

संक्रमण का खतरा

नाखून चबाने से बच्चों के हाथों से बैक्टीरिया मुंह में जा सकते हैं। यदि बच्चे अपनी उंगलियों को मुंह में डालते हैं और नाखून चबाते हैं, तो यह बैक्टीरिया उनके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इससे गले में इंफेक्शन, मौखिक रोग, या पेट में समस्याएँ हो सकती हैं। खासकर अगर बच्चा गंदे हाथों से नाखून चबाता है तो यह और भी खतरनाक हो सकता है।

पाचन तंत्र पर प्रभाव

नाखून चबाने से कुछ बच्चे नाखूनों को निगलने की भी आदत डाल सकते हैं। यदि यह नाखून अंदर पेट में चले जाते हैं, तो यह पाचन तंत्र में अड़चन पैदा कर सकते हैं। इससे पेट की समस्याएँ, जैसे गैस, कब्ज, या आंतों की समस्याएँ हो सकती हैं।

मानसिक तनाव और चिंता

नाखून चबाना कभी-कभी मानसिक तनाव या चिंता का संकेत भी हो सकता है। कई बार बच्चे तब नाखून चबाते हैं जब वे किसी समस्या या चिंता से जूझ रहे होते हैं। यदि यह आदत लगातार बनी रहती है, तो यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है। ऐसे में बच्चे को मानसिक शांति और समर्थन की आवश्यकता होती है, ताकि वह इस आदत से छुटकारा पा सके।

कैसे छुड़ाएं आदत

1 बच्चों को नाखून चबाने से रोकने के लिए सबसे पहले माता-पिता को सकारात्मक वातावरण और प्यार देना चाहिए। बच्चों को समझाना और शांतिपूर्वक बताना कि यह आदत कितनी हानिकारक हो सकती है, उनके लिए सहायक हो सकता है।

2 यदि बच्चे की नाखून चबाने की आदत मानसिक तनाव या चिंता के कारण हो रही है, तो एक अच्छे मनोचिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। बच्चे को मानसिक शांति देने के लिए ध्यान, योग, और अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं।

3 बच्चों को हमेशा साफ हाथों से भोजन करना और मुंह की सफाई पर ध्यान देने की सलाह दें। साथ ही, बच्चों के नाखूनों की सफाई और नियमित काटने का ध्यान रखें।

4 बच्चों को अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखना भी उनकी नाखून चबाने की आदत को कम कर सकता है। जैसे कि खेलकूद, चित्रकला, संगीत आदि।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

काश पटेल और तुलसी गबार्ड हो सकते है ट्रंप के अगले शिकार?

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को बर्खास्त कर दिया है। अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के निदेशक काश पटेल का अगला नंबर हो सकता है। इसके साथ ही एफबीआई के भीतर चल रहे विवादों और ट्रंप प्रशासन में कई अन्य बड़े बदलावों की अटकलों ने भी तूल पकड़ लिया है। खबरों की मानें तो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो सकता है जिन्हें ट्रंप प्रशासन हटाने वाला है। एक दिन पहले ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया है। पेंटागन ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि जनरल जॉर्ज तत्काल प्रभाव से सेना के 41वें प्रमुख के पद से रिटायर हो रहे हैं।

काश पटेल की संभावित विदाई : पूर्व एफबीआई एजेंट काइल सेराफिन ने दक्षिणपंथी होस्ट एलेक्स जोंस से बातचीत में सूत्रों के हवाले से एफबीआई में बड़े बदलाव का दावा किया है। सेराफिन के अनुसार इस बात की काफी संभावना है कि काश पटेल को आज ही बर्खास्त कर दिया जाए और विभाग में पूरी तरह से नया फेरबदल

किया जाए। सेराफिन ने आगे कहा कि सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा अनुमान है कि ट्रंप इसे इस तरह से पेश करना चाहते हैं कि यह उनका अपना फैसला है, न कि किसी दबाव के कारण उठाया गया कदम।

एफबीआई में 'प्रतिशोध अभियान' और पूर्व एजेंटों का मुकदमा : काश पटेल के नेतृत्व में एफबीआई में बड़े पैमाने पर हुई छंटनी के खिलाफ अब कानूनी चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। इस हफ्ते तीन पूर्व एफबीआई एजेंटों ने अपनी बहाली की मांग करते हुए एक 'क्लास-एक्शन' मुकदमा दायर किया है। इन एजेंटों का दावा है कि 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने के ट्रंप के प्रयासों की जांच में शामिल होने के कारण उन्हें अवैध रूप से दंडित किया गया है। पिछले एक साल में काश पटेल के नेतृत्व में दर्जनों एजेंटों को पद से हटाया गया है। इनमें से कई को ट्रंप से जुड़ी जांचों में शामिल होने के कारण या रिपब्लिकन राष्ट्रपति के एजेंडे के प्रति अपर्याप्त रूप से वफादार माने जाने के कारण बर्खास्त किया गया था।

एजेंट और उनका बेदाग रिकॉर्ड : मिशेल बॉल, जेमी गारमन और ब्लेयर टोलमैन नाम के इन तीन एजेंटों को पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में निकाल दिया गया था। मुकदमे के अनुसार, इन तीनों के पास 8 से 14 साल का 'शानदार और बेदाग' सर्विस रिकॉर्ड था। उन्हें उम्मीद थी कि वे अपना पूरा करियर एफबीआई में बिताएंगे, लेकिन उन्हें बिना किसी कारण बताए या अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही अचानक बर्खास्त कर दिया गया। इन एजेंटों ने अपनी बर्खास्तगी को ट्रंप पर की गई उनकी जांच के खिलाफ एक 'प्रतिशोध अभियान' करार दिया है।

प्रशासन में अन्य संभावित बदलाव: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रशासन में कुछ और अहम पदों पर भी बदलाव करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रशासक ली जेल्डिन को पाम बोंडी की जगह नए अटॉर्नी जनरल के संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा, नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड को भी उनके पद से हटाने को लेकर प्रशासन के भीतर चर्चा चल रही है। यह पूरा घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर एक व्यापक पुनर्गठन चल रहा है। एफबीआई में वफादारी और पुरानी जांचों को लेकर चल रही उथल-पुथल के बीच कई बड़े अधिकारियों और एजेंटों की छंटनी की जा रही है, जो अब कानूनी मुकदमों का रूप ले रही है।

ऑस्ट्रेलिया ने दवाइयों पर शुल्क लगाने के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत से किया इनकार

कैनबरा , एजेंसी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के दबाव के बावजूद दवाओं के लिए अपनी सब्सिडी योजना में कोई बदलाव नहीं करेगी। स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने शुक्रवार को सरकार का पक्ष रखा। बटलर ने सेवन नेटवर्क को बताया कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी प्रशासन के साथ फार्मास्युटिकल बेनेफिट्स स्कीम (पीबीएस) के 'मूलभूत सिद्धांतों' पर कोई बातचीत नहीं करेगा। इस योजना के तहत केंद्रीय सरकार प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतों में सब्सिडी देती है।

बटलर ने कहा, 'हम अमेरिका को यह सबसे स्पष्ट संदेश लगातार भेज रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वहां बड़ी दवा कंपनियां अपने दबाव में हमारे पीबीएस और दुनिया के अन्य देशों की समान योजनाओं को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। हम इन मूलभूत सिद्धांतों पर बातचीत नहीं कर रहे हैं।' बटलर यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कुछ पेटेंट वाली दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद दे रहे थे।

मार्च के अंत में ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक शिकायतों की अद्यतन सूची में अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि पीबीएस अमेरिकी नवाचार का मूल्य कम करके दिखाता है और अनुचित दवा मूल्य निर्धारण प्रथाओं के माध्यम से अमेरिकी उद्योग को प्रभावित करता है। इस योजना के तहत, फार्मास्युटिकल निर्माता सीधे ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ बिक्री पर बातचीत करते हैं ताकि वाणिज्यिक बोली युद्धों को रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र के कॉमट्रेड डेटा के अनुसार, 2025 में ऑस्ट्रेलियाई दवा निर्यात अमेरिका में 1.3 बिलियन डॉलर का था। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी सीएसएल ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी है, लेकिन बटलर ने कहा कि सरकार को भरोसा है कि मेलबर्न स्थित इस कंपनी को नए शुल्क से छूट मिलेगी क्योंकि इसका अमेरिका में बड़ा उत्पादन आधार है। व्यापार मंत्री डॉन फैरेल के प्रवक्ता ने आस्ट्रेलियन ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन को शुक्रवार को बताया कि सरकार अमेरिकी दवा शुल्क से निराश है और 'अनुचित और गैर-जरूरी' शुल्क को हटाने के लिए दबाव डालना जारी रखेगी।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निजी हथियार रखने की अनुमति

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब सैनिकों को सैन्य ठिकानों पर अपने निजी हथियार रखने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक नया आदेश जारी किया जा रहा है, जिसके तहत सैनिक अपने सुरक्षा कारणों से हथियार रखने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि किसी सैनिक की मांग ठुकराई जाती है, तो अधिकारियों को लिखित रूप में कारण बताना होगा। अब तक सैन्य ठिकानों को लगभग गन-फ्री जोन माना जाता था, जहां केवल सैन्य पुलिस या ट्रेनिंग के दौरान ही हथियार रखने की अनुमति थी। इस फैसले के पीछे हाल के वर्षों में सैन्य ठिकानों पर हुई गोलीबारी की घटनाएं बड़ी वजह मानी जा रही हैं। हेगसेथ का कहना है कि ऐसे मामलों में शुरुआती कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सैनिकों को अपनी सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि इस फैसले को लेकर सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि इससे हथियारों की संख्या बढ़ेगी। रक्षा विभाग पहले से ही हथियारों के इस्तेमाल और स्टोरेज को लेकर सख्त नियम लागू करता रहा है।

अमेरिका से निर्वासित लोगों का पहला जत्था युगांडा पहुंचा

कंपाला, एजेंसी। अमेरिका से निकाले गए 12 लोगों का पहला समूह युगांडा पहुंच गया है। यह घटना उस समझौते के बाद हुई है, जो अमेरिका और युगांडा के बीच हुआ था। युगांडा लॉ सोसाइटी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन लोगों को बहुत ही अपमानजनक और अमानवीय तरीके से लाया गया। बताया गया कि इन्हें एक निजी विमान से लाया गया और उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति का हिस्सा है, जिसमें अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। खासतौर पर उन लोगों को, जिनको उनके अपने देश वापस नहीं लिया जा सकता। युगांडा के एक मंत्री ने कहा था कि उनका देश ऐसे अफ्रीकी मूल के लोगों को मानवीय आधार पर स्वीकार करेगा, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि जो लोग आए हैं, वे किन देशों के हैं। इस पूरे मामले को लेकर युगांडा में कानूनी चुनौती भी दी जा रही है। कई लोग इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मान रहे हैं और इसे रोकने की मांग कर रहे हैं।

तीन अमेरिकी राज्यों के खिलाफ मुकदमा दायर

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में प्रेडिक्शन मार्केट को लेकर अब बड़ा कानूनी विवाद शुरू हो गया है। सरकार ने तीन राज्यों, कनेक्टिकट, एरिजोना और इलिनोइस, के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यह विवाद उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लेकर है, जहां लोग भविष्य की घटनाओं (जैसे चुनाव या अन्य नतीजों) पर पैसा लगाते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स में कालशी और पॉलीमार्केट जैसे नाम शामिल हैं। दरअसल, इन तीनों राज्यों ने इन कंपनियों को नोटिस भेजकर कहा था कि वे गैरकानूनी ऑनलाइन जुए में शामिल हैं और तुरंत अपना काम बंद करें। एरिजोना ने तो पिछले महीने कालशी के खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज कर दिया था, क्योंकि वहां चुनावों पर सट्टा लगाना कानून के खिलाफ है। लेकिन अब सरकार की एजेंसी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने कोर्ट में कहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं, बल्कि उनके पास है। सीएफटीसी का कहना है कि अगर हर राज्य अपने हिसाब से नियम बनाएगा, तो इससे धोखाधड़ी और उपभोक्ताओं के लिए खतरा बढ़ सकता है। वहीं, ट्रंप सरकार ने भी कालशी और पॉलीमार्केट जैसे प्लेटफॉर्म्स का समर्थन किया है। इससे यह मामला और ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि इसका असर भविष्य में ऑनलाइन सट्टेबाजी और स्पोर्ट्स बेटिंग के नियमों पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ, कनेक्टिकट के अटॉर्नी जनरल विलियम टोंग ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कंपनियां साफ तौर पर गैरकानूनी जुआ चला रही हैं।

नेपाल : ओली और रमेश लेखक की हिरासत दो दिन बढ़ी, जांच जारी

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई है। काठमांडो जिला अदालत के न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थी की एकल पीठ ने जांच के लिए यह अनुमति दी। ओली के अस्पताल में भर्ती होने के कारण उनकी पेशी वर्चुअल माध्यम से की गई। इससे पहले रविवार को अदालत ने दोनों को पांच दिन की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। यह अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने और समय की मांग की थी। गौरतलब है कि जेनजी आंदोलन की घटनाओं की जांच के लिए गठित गौरीबहादुर कार्की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दोनों नेताओं को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।

चीन के नए परमाणु केंद्र में बनीं इमारतें: गुप्त योजनाओं की आशंका, तस्वीरों में दिखी यूरेनियम संवर्धन की मशीनें

बीजिंग, एजेंसी। एक तरफ दुनिया में कई विकसित देश अपना रक्षा बजट बढ़ाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहे हैं वहीं चीन लगातार अपने परमाणु हथियार सुविधाएं तेज करने में जुटा है। उसने भारत से करीब 1,400 किमी दूर सिचुआन प्रांत में कुछ गावों को खाली करवाकर एक बड़ी परमाणु सुविधा बनाई है। फरवरी के अंत में उपग्रह चित्रों से इसका खुलासा होने के बाद अब जानकारी मिली है कि यहां पर चीन ने कुछ नई इमारतों का निर्माण भी पूरा कर लिया है। ताजा उपग्रह चित्रों से पता चला है कि चीन ने अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की गुप्त योजनाओं को अमल में लाना शुरू कर दिया है। यहां जिन इमारतों का निर्माण हो चुका है उनमें रेडिएशन मॉनिटर व धमाका रोधी दरवाजे लगे होने तथा यूरेनियम और प्लूटोनियम के लिए मशीनें लगने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। उपग्रह तस्वीरों में साइट पर दिख रहे बड़े बड़े ट्रालों में रखीं मशीनों की मौजूदगी से इनके यूरेनियम या प्लूटोनियम होने की आशंका जताई जा रही है। चीन ने इस जगह को साइट-906 नाम दिया है। फरवरी मध्य और मार्च अंत में दिखे उपग्रह चित्र बताते हैं कि इस साइट पर काम उम्मीद से अधिक तेजी से हो रहा है। इसे 3 अन्य एटमी ठिकानों से जोड़ा गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में जब इस परमाणु सुविधा के लिए जमीन खाली कराई गई तो कुछ ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर पूछा था कि सरकार उनकी जमीन क्यों जब्त कर रही है? इस पर अधिकारियों ने इसे सरकार की गुप्त योजना बताया था। लेकिन चार साल बाद जो उपग्रह चित्र मिले हैं वह बताते हैं कि चीन ने यहां गांव खाली करवाकर बड़ी ही तेजी से परमाणु सुविधाओं के विकास का निर्माण ढांचा तैयार किया है। सिचुआन प्रांत का दुर्गम-कठिन पहुंच वाला स्थान चुना चीन का सिचुआन प्रांत अपनी भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है। पूर्व में उपजाऊ, घनी आबादी वाला सिचुआन बेसिन और पश्चिम में ऊबड़-खाबड़ तिब्बती पठार तथा हेंगडुआन पर्वत मौजूद है। यहां यांग्जी नदी और उसकी सहायक मिन, तुओ और जियालिंग व टोंगजियांग नदियों के किनारे पर यह सुविधा विकसित की गई है।

2030 तक चंद्रमा पर स्थायी ठिकाना स्थापित करने को लेकर अमेरिकी विधेयक पेश

वॉशिंगटन , एजेंसी। एक अमेरिकी सांसद ने ऐसा विधेयक पेश किया है, जिसमें नासा को 2030 तक चंद्रमा पर स्थायी ठिकाने के प्रारंभिक ढांचे स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। उनका कहना है कि यह कदम अंतरिक्ष में चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका की नेतृत्व भूमिका बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कीथ सेल्फ ने नासा को 2030 तक चंद्रमा पर स्थायी ठिकाने की स्थापना के लिए निर्देशित करने वाला विधेयक पेश किया, जो आर्टेमिस II मिशन के प्रक्षेपण के एक दिन बाद सामने आया। यह मिशन पांच दशकों से अधिक समय में पहली मानवयुक्त उड़ान है जो चंद्र कक्षा तक गई। इस प्रस्ताव का उद्देश्य मौजूदा अमेरिकी अंतरिक्ष कानून में संशोधन करना है और 31 दिसंबर 2030 तक प्रारंभिक ठिकाना स्थापित करने की समयसीमा तय करता है।

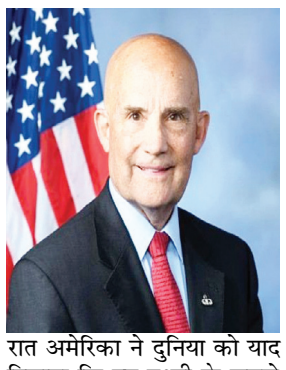

कीथ सेल्फ ने कहा, 'कल रात अमेरिका ने दुनिया को याद दिलाया कि हम पृथ्वी के सबसे महान अंतरिक्ष यात्री देश हैं लेकिन जश्न मनाना कोई रणनीति नहीं है। अगर हमें अंतरिक्ष में अपनी नेतृत्व भूमिका बनाए रखनी है, तो हमें चंद्रमा पर स्थायी रूप से मानव उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

विधेयक के अनुसार, नासा प्रशासक को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर प्रारंभिक बुनियादी ढांचा स्थापित करना होगा। यह क्षेत्र जल-बर्फ की मौजूदगी के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे रॉकेट ईंधन में बदला जा सकता है। साथ ही, यहां हीलियम-3 और दुर्लभ खनिज भी पाए जाते हैं। सेल्फ ने इस मिशन को आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, 'चंद्रमा केवल एक गंतव्य नहीं है बल्कि यह एक नए औद्योगिक युग की नींव है। यहां के संसाधन अंतरिक्ष निर्माण, खनन और निर्माण कार्यों की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां पहले से ही इस दिशा में तकनीक विकसित कर रही हैं लेकिन उन्हें सरकार के निरंतर समर्थन और चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति की जरूरत है। यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दशक के अंत तक चंद्रमा के इसी क्षेत्र में एक अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। सेल्फ ने कहा, 'चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अंतरिक्ष में हमारा साझेदार नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी है और वह जीतने के इरादे से आगे बढ़ रही है। चंद्र संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय कानून अभी स्पष्ट नहीं है। जो देश पहले वहां स्थायी उपस्थिति स्थापित करेगा, वही नियम तय करेगा। 'आर्टेमिस II मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री ओरियन स्पेसक्राफ्ट के जरिए चंद्रमा के पास से गुजरेंगे। यह 1972 के बाद पहला मानवयुक्त गहरे अंतरिक्ष का मिशन है। सेल्फ का मानना है कि स्थायी चंद्र ठिकाना अमेरिका के लिए आर्थिक लाभ भी लाएगा। उन्होंने कहा, 'चंद्रमा पर ठिकाना बनने से अमेरिका में रोजगार, नवाचार और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा मिलेगा। नेतृत्व करने का यह मौका खुला है और यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि हम इसे गंवाएं नहीं।' यह प्रस्ताव पहले नासा रिएथराइजेशन एक्ट के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, जिसे फरवरी में समिति की मंजूरी मिली थी और अब इसे एक अलग विधेयक के रूप में दोबारा पेश किया गया है।

पाकिस्तान में डीजल 520 रुपये लीटर हुआ, पेट्रोल भी 450 के पार

इस्लामाबाद, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश में लगा पाकिस्तान बड़े तेल संकट से जूझ रहा है। इसके चलते मुल्क में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। शुक्रवार से ये नए दाम प्रभावी हो जाएंगे। बीते महीने भी पाकिस्तान ने कीमतों में करीब 20 प्रतिशत का इजाफा किया था।

अब क्या हैं रेट : पाकिस्तान ने गुरुवार को डीजल की रेट बढ़ाकर 520.35 रुपये (पाकिस्तानी रुपया) प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 458.40 रुपये प्रति लीटर कर दीं। एक ओर जहां डीजल रेट 54.9 फीसदी बढ़े हैं। वहीं पेट्रोल में 42.7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से यह कदम उठाया गया।

सरकार ने युद्ध को बताया जिम्मेदार : पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने इसका जिम्मेदार कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों को बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, 'अमेरिका और ईरान युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें नियंत्रण के बाहर चली गईं हैं। ऐसे में रेट बढ़ने ही थे।'

कराची पहुंचा एक जहाज : बुधवार को ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकला एक जहाज कराची पोर्ट पहुंचा था। ट्रस्ट के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि इसके अलावा एक दूसरा जहाज भी दूसरे मार्ग से बंदरगाह पर पहुंचा है। प्रवक्ता शारिक फारूकी ने कहा कि इस महीने खाड़ी देशों से जरूरी तेल की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान के झंडे वाले और भी जहाजों के आने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि ईरान होर्मुज से 20 अतिरिक्त पाकिस्तानी जहाजों को गुजरने देने पर सहमत हो गया है।

चीन के साथ मिलकर दिया प्लान : चीन और पाकिस्तान ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए पांच सूत्री प्रस्ताव रखा है। इन प्रस्तावों में शत्रुता को तुरंत समाप्त करने, जल्द से जल्द शांति वार्ता शुरू करने, गैर-सैन्य लक्ष्यों की सुरक्षा और नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को मानने जैसे प्रावधान शामिल थे।

अमेरिका में भी महंगी हुई गैस : पश्चिमी एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका में औसत उपभोक्ता के लिए गैस की कीमतों में 35 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। कीमतों की इस वृद्धि से हाल बहुत जल्द राहत मिलने की भी उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि होर्मुज कुछ देशों के जहाजों को छोड़कर सभी के लिए बंद है। होर्मुज का बंद होना वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को खासा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इस मार्ग से दुनिया के तेल का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है।

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सेना प्रमुख को पद छोड़ने का दिया आदेश

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को तत्काल पद छोड़ने और सेवानिवृत्त होने का निर्देश दिया है। रक्षा मंत्री के इस आदेश के बाद जनरल जॉर्ज ने प्रभावी रूप से अपना पद त्याग दिया है। ईरान के साथ जारी भीषण तनाव के बीच, हेगसेथ का यह कड़ा फैसला पेंटागन में बड़े प्रशासनिक फेरबदल का संकेत दे रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने एक बयान में कहा, 'जनरल रैंडी ए. जॉर्ज आर्मी के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के पद से तत्काल प्रभाव से रिटायर हो रहे हैं। रक्षा विभाग देश के लिए उनकी दशकों की सेवा के लिए उनका आभारी है और उनके रिटायरमेंट के लिए शुभकामनाएं देता है।' अमेरिकी सेना और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हेगसेथ ने जॉर्ज से पद छोड़ने के लिए कहा था। उनकी जगह सेना के उप सेनाध्यक्ष जनरल क्रिस्टोफर लानेव जिम्मेदारी संभालेंगे। जनरल क्रिस्टोफर लानेव सीनेट से उनके उत्तराधिकारी की पुष्टि होने तक एक्टिंग चीफ के तौर पर काम करेंगे।

हता दें, जनरल रैंडी ए. जॉर्ज सितंबर 2023 में सेना के प्रमुख बने थे, उनके पास आम तौर पर चार साल के कार्यकाल में लगभग डेढ़ साल बाकी थे। हेगसेथ के ऑफिस संभालने के बाद जॉर्ज पद छोड़ने वाले सबसे नए वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बन गए हैं। यह बदलाव सिर्फ एक पोस्ट से कहीं ज्यादा है। रिपोर्टिंग में बताए गए रक्षा अधिकारियों के मुताबिक, जॉर्ज के साथ दो और आर्मी जनरलों को भी हटा दिया गया, जिनमें ट्रेनिंग और चैपलेंसी के काम देखने वाले वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इस कदम पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेसी यूजीन विंडमैन ने कहा, 'जनरल रैंडी जॉर्ज एक जबरदस्त पब्लिक सर्वेंट और सैनिक हैं। यह निराशाजनक है कि उनके जैसे अधिकारी को इसलिए किनारे कर दिया गया क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसा आदमी चाहते हैं जो उनकी हां में हां मिलाए। विंडमैन ने पेंटागन लीडरशिप की भी आलोचना करते हुए कहा, 'अगर पेंटागन में नेतृत्व की गुणवत्ता पर सवाल हैं, तो ये सवाल सेक्रेटरी हेगसेथ को लेकर उठाया जाना चाहिए, न कि उन पर जिन्होंने अपना करियर सम्मान के साथ हमारे देश की सेवा में बिताया है।' यह बदलाव अमेरिकी सेना में बड़े तनाव के बीच हुआ है। इसके अलावा, हेगसेथ ने हाल ही में एक अपाचे हेलीकॉप्टर क्रू से जुड़ी एक घटना में दखल देकर विवाद खड़ा कर दिया था। इस घटना से जुड़ा सस्पेंशन हटाने के बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'कोई सजा नहीं। कोई जांच नहीं। देशभक्तों, आगे बढ़ो।' पेंटागन ने जॉर्ज को हटाने के पीछे के कारणों के बारे में डिटेल में नहीं बताया है। सेना प्रमुख का पद अमेरिका में सबसे सीनियर सैन्य पदों में से एक है।

अमेरिका में बड़ा हेल्थकेयर घोटाला, पचास मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का भंडाफोड़

कैलिफोर्निया , एजेंसी। अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसने पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के तहत कैलिफोर्निया में एफबीआई ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने झूठे होस्पिस केयर केंद्र चलाकर मेडिकेयर से करीब 50 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की। आरोपियों में नर्स, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और कायरोप्रैक्टर शामिल हैं। जांच में पता चला कि मरीजों को वास्तविक टर्मिनल बीमारी के बिना दाखिल कर बिल बनाया गया, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली और टैक्सदाताओं को भारी नुकसान हुआ। बता दें कि यह कार्रवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स टू एलीमिनेट फ्रॉड के सहयोग से की गई। एफबीआई और अभियोजन के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों में तीन नर्सें, एक डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट और एक कायरोप्रैक्टर शामिल हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने ऐसे मरीजों को होस्पिस में दाखिल कर बिल बनाया, जिनकी वास्तव में टर्मिनल बीमारी नहीं थी। आमतौर पर होस्पिस में लोग जीवन के अंतिम चरण में जाते हैं, लेकिन इन केंद्रों में मरीजों की जीवित रहने की दर राष्ट्रीय औसत 17% से पांच गुना ज्यादा थी।

मुख्य आरोपियों में कौन-कौन है- ग्लैडविन और एमेलौ गिल- 626 होस्पिस के मालिक, जिन पर 5.2 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने और गैरकानूनी किकबैक देने का आरोप। लोलीता बेरोनिला मिनर्ड- टोपांगा होस्पिस की मालिक, जिन पर 9 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप। सोनिया ग्रिफेन- हेल्थकेयर फ्रॉड में पांच मामलों में आरोपित। ग्रेगरी कार्टमेल- कायरोप्रैक्टर, हेल्थकेयर फ्रॉड और आईडेंटिटी चोरी के

आरोप में गिरफ्तार। इवान वर्न लॉरिट्जन- वैली पैसिफिक होस्पिस के सीईओ और सीएफओ, जिनकी मेडिकेयर एनरोलमेंट 2024 में रद्द हो चुकी थी।नीता अल्मुएटे पट्टिट पाल्मा और पति अदोल्फो कैटबैगन- तीन झूठे होस्पिस केंद्र चलाने और वायर फ्रॉड करने के आरोप। एफबीआई के सहायक निदेशन ने दी जानकारी मामले में एफबीआई के लॉस एंजिलेस क्षेत्र के सहायक निदेशक अकील डेविस ने कहा कि दक्षिण कैलिफोर्निया हेल्थकेयर धोखाधड़ी के लिए उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। अमेरिका हर साल हेल्थकेयर धोखाधड़ी में सैकड़ों अरब डॉलर खो देता है, जिससे आम लोगों के बीमा प्रीमियम और टैक्स बढ़ते हैं। ऐसे में अब यह मामला अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और झूठे होस्पिस संचालन की गंभीरता को उजागर करता है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

REG. NO. A/3229/SRT

स्थापना :- 2003

श्री घण्टियाला बालाजी मंडल (रजि.) - सुरत द्वारा आयोजित

17th ANNIVERSARY

श्री हनुमान जन्मोत्सव

भजन गायिका आशाजी वैष्णव

सभी धर्म प्रेमी को अत्यंत हर्ष के साथ सुचित किया जाता है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन बडे ही धुम धाम के साथ होने जा रहा है जिसमें आप सभी भक्त सपरिवार सादर आमंत्रित है।

दिनांक :- 05 अप्रैल 2026, रविवार

समय :- शाम 06 :15 बजे से प्रभु इच्छा तक

अखण्डज्योत, छप्पन भोग विशाल भजन संध्या सवामणी एवं महाप्रसादी

नोट:: किसी भक्त को सवामणी में अपना नाम लिखवाना हो तो मण्डल से सम्पर्क करें

स्थान ::

श्री घण्टियाला बालाजी धाम लेन्डमार्क एम्पायर मार्केट, सुरत-कडोदरा रोड, सारोली, सुरत

सम्पर्क सुत्र :

98254 80565, 9327044077

नोट:- मण्डल द्वारा हर शनिवार को संगीतमय श्री सुन्दरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है।

विशिष्ठ अतिथी ::

श्री माधवजी भाई पटेल
(MD'S LANDMARK)
श्री ललीत कुमारजी शाह
(Global Textile Market)
सुखा भाई लुनी
(Radiant Blue)
श्री जोगेन्द्र भाई साहनी
(अध्यक्ष अंतराट्रीय हिन्दू परिषद, सूरत)
श्री विकमसिंहजी भाटी
(मंत्री विश्व हिन्दू परिषद, सूरत)
श्री शैलेशभाई गंगाणी
(Sanskar Group) (उद्योगपति)

:: मुख्य अतिथी ::

श्री रूपकजी त्रिपाठी
(RT'S MEDIA)
ॐ श्री ओमप्रकाशजी शर्मा
(Chetas.Creation)
श्री मांगीलालजी मालु
(RPH Developers)
श्री राधेश्यामजी राठी
(Maa Fashion)
श्री विनोदजी राठी
(Vivek Silk Mills)
श्री ललीतजी चाण्डक
(Pari Cotton LLP)
श्री अशोकजी राठी
(Gokul Textile)
श्री राजुभाई जयसिंह
(Sai Ansh)
श्री सुरेशजी राठी : (Khushali Group)

:: सम्मानीय अतिथी ::

श्री मेघराजजी गांधी
(RMG SCHOOL)
श्री प्रविणजी पनपालीया
(Hare Krishna)
श्री मनोजजी गांधी
M.L. Creation
श्री भगवानजी चाण्डक
(Divya Fab Int. P. Ltd)
श्री दिनेशजी सोनी
(Real Estate)
दिलिपजी लाठिया
SinSim Liberty
श्री मनिषजी गांधी
(L.K. Fab)
श्री मदनलालजी राठी
(M.L. Rathi)
तुषार भाई पैठानी
Anjani Group

:: सम्मानीय अतिथी ::

श्री निर्मलजी जैन
(saket Textile)
श्री रणजीत कुमार जी पटेल
(Ram Rasayan Digital)
श्री गोविन्दजी शर्मा
(Shree Art)
श्री गौरवजी डागा
(Gaurav Textile)
श्री कमल किशोरजी लद्धद
(श्याम धणी मंडप)
श्री मोहनसिंहजी राजपुरोहित
(Vijay Shakti Caterers)
श्री हरिसिंहजी उगरारामजी
(Karni Digital)
श्री नानुभाई
(Vinayak Poli Plast)
श्री जयप्रकाश जी
(Chirag Tex Fab)
श्री समीर भाई त्रिपाटी
(Image Video Films)
श्री अमरचन्दजी राठी
(Mamaji Estate)
श्री सोनु खण्डेलवाल
(Samaj Seva)
श्री मनोजजी नानवटी
(Shilp Art)
श्री प्रफुलचन्दजी बोराणा
(Sunasi Befining Luxury)
श्री गणपतजी स्वामी
(VGM Creation)
श्री अतुल जी पुजारा
(Pujara Enterprise)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

तिरंगा लगे जहाज ने होर्मुज जलडमरूमध्य किया पार, अब भी 17 भारतीय जहाज फंसे

भारत पहुंचने पर एलपीजी को लेकर चल रही किल्लत से मिलेगी राहत

नई दिल्ली ।

मिडिल ईस्ट संकट के बीच शुक्रवार को सातवां भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर, ग्रीन सानवी, होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर गया। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक छह एलपीजी ले जाने वाले जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार करके भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं। अब सातवां टैंकर भी होर्मुज क्रॉस करके भारत की ओर बढ़ रहा है। इस जहाज पर करीब 44,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी है। इसके आने से एलपीजी को लेकर चल रही किल्लत से राहत मिलेगी। होर्मुज के पश्चिम में अब भी 17 भारतीय जहाज फंसे हैं। इनमें दो एलपीजी से लदे जहाज ग्रीन आशा और जग विक्रम हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक एलपीजी से लदे ये दोनों जहाज ग्रीन आशा और जग विक्रम भी जल्द ही होर्मुज से निकलकर भारत की ओर रवाना हो सकते हैं। जानकारों ने बताया कि तीन एलपीजी ले जाने वाले भारतीय जहाज वर्तमान में फारस की खाड़ी स्थित अबू मूसा द्वीप के उत्तर-पूर्व में भटक रहे हैं। वे भारतीय नौसेना के निर्देशों का पालन करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य से निकलने के आदेश की प्रतीक्षा में हैं।

इस बीच एक विदेशी जहाज, जो कथित तौर पर ईरान से भारत के लिए तेल ले जा रहा था, उसने अपनी यात्रा के दौरान ही अपना डेस्टिनेशन प्वाइंट अचानक बदल दिया। अब वह चीन की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक विश्लेषण फर्म केप्लर के प्रमुख विश्लेषक ने कहा कि ईरानी कच्चे तेल के मामले में इस तरह की यात्रा के दौरान गंतव्य परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। यह वित्तीय शर्तों और काउंटर पार्टी रिस्क के प्रति ट्रेड फ्लो की बढ़ती संवेदनशीलता को उजागर करता है। एक्सपर्ट ने कहा कि कच्चा तेल लेकर जा रहे शिप के अचानक चीन की ओर मुड़ने के बीच अहम वजह पेमेंट का माना जा रहा। इसमें पहले की 30-60 दिन की लोन अवधि से हटकर अग्रिम या निकट-अवधि के सेटलमेंट की ओर बढ़ रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भुगतान संबंधी समस्याएं हल हो जाती हैं, तो माल अभी भी किसी भारतीय रिफाइनरी तक पहुंच सकता है। विश्लेषक ने आगे कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि चीन के अलावा अन्य देशों में ईरानी कच्चे तेल के प्रवाह को निर्धारित करने में वाणिज्यिक शर्तें रसद के समान ही अहम होती जा रही हैं। हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कच्चे तेल से लदे इस शिप का फाइनल डेस्टिनेशन यही रहने वाले है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तो ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन ट्रांसपोंडर में

दर्शाया गया है ये गंतव्य अंतिम है और यात्रा के दौरान इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, इसमें आगे भी बदलाव हो सकते हैं। वहीं अगर ये टैंकर वास्तव में वडीनार पहुंच जाता, तो यह छह सालों में भारत को ईरान से कच्चे तेल की पहली खेप होती।

चूड़धार के लिए अवैध सड़क का निर्माण.....हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

शिमला ।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चौपाल क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध सड़क निर्माण की शिकायत पर संज्ञान लेकर सरकार से जवाब तलब किया है। चौपाल डिवीजन के घने देवदार के जंगल में चूड़धार के लिए पांच किलोमीटर लंबी वाहन योग्य सड़क का अवैध रूप से निर्माण हुआ है। इस संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर दर्ज जनहित याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया भारद्वाज की खंडपीठ ने हिमाचल सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के अंदर जबाव मांगा है। यह सड़क चूड़धार स्थित शिरगुल महाराज के निवास स्थान की ओर जाती है। देवदार के घने जंगल में सड़क निर्माण के दौरान कई पेड़ों के भी कटने का अंदेशा है, इस कारण हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर प्रदेश सरकार से तय समय में जवाब तलब किया है। शिकायत में उल्लेख हैं कि चूड़धार पर्वत और उसके आसपास के जंगल न केवल पारिस्थितिक संपदा हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा गहराई से आदर किया जाने वाला एक पवित्र सांस्कृतिक परिदृश्य भी है। मोटर योग्य सड़क के निर्माण से क्षेत्र में अनियंत्रित पर्यटन और कारोबारी शोषण होगा, जिससे शोर, प्रदूषण, अशांति, अतिक्रमण और अपशिष्ट उत्पादन होगा। आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से कुछ परियोजनाओं के तहत प्राप्त धन पारिस्थितिक संरक्षण और सतत वन प्रबंधन के लिए है, न कि उन गतिविधियों के लिए जो वनों और राज्य की पारिस्थितिक अखंडता को नुकसान पहुंचाती हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने चेताया कहा- नया अतिक्रमण हुआ तो क्षेत्रीय अधिकारी पर एक्शन होगा

देहरादून ।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर दोहराया है कि राज्य की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाना किसी विशेष वर्ग को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि यह देवभूमि की जनसांख्यिकी, सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक सौंदर्य को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया अनिवार्य कदम है। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी भी क्षेत्र में नया अतिक्रमण पनपता हुआ पाया गया, तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अधिकारी को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी शुक्रवार को नगर निगम में चार करोड़ रुपये की विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने नवनिर्मित 'जुगमंदर हॉल' का उद्घाटन करते हुए इसे राज्य की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। प्रदेश के विकास का खाका खींचते हुए उन्होंने राजधानी के आधुनिक कायाकल्प के लिए 1400 करोड़ रुपये की विशाल योजनाओं का विजन साझा किया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद शहर पर आबादी और वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाएगा। इस दबाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार अभी से आवास, मल्टीलेवल पार्किंग और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर काम कर रही है ताकि देहरादून एक आदर्श राजधानी के रूप में विकसित हो सके। कार्यक्रम के दौरान शहरी विकास मंत्री और अन्य कैबिनेट

मंत्रियों ने भी शहर की स्वच्छता रैंकिंग और बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया। नगर निगम द्वारा इस वर्ष की गई 72 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड टैक्स वसूली को विकास कार्यों के लिए एक सकारात्मक संकेत बताया गया। दूसरी ओर, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। उन्होंने मुख्य रूप से पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाने, पार्षदों के लिए स्वास्थ्य बीमा और सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने जैसे मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा।

ट्रंप ने दवाओं पर लगाया 100 प्रतिशत टैरिफ, भारत पर नहीं पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रांडेड दवाओं और उनके घटकों (इनग्रेडिएंट्स) पर 100 फीसदी आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने के फैसले ने वैश्विक बाजार में हलचल मचा दी है। ईरान के साथ बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच ट्रंप के इस कड़े आर्थिक कदम को टैरिफ मिसाइल के तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि, भारतीय दवा उद्योग के लिए राहत की खबर यह है कि इस भारी-भरकम टैक्स का भारत पर कोई सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति का असर केवल उन कंपनियों और देशों पर होगा जो ब्रांडेड दवाओं का निर्माण, खरीद और बिक्री करते हैं। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के

अनुसार, भारत को इस फैसले से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारतीय दवा उद्योग की मजबूती जेनेरिक दवाओं में निहित है।

भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है और अमेरिका अपनी जरूरतों के लिए भारत से मुख्य रूप से इन्हीं किफायती दवाओं का आयात करता है। चूंकि ट्रंप का नया टैरिफ आदेश विशेष रूप से ब्रांडेड दवाओं और उनके कच्चे माल पर केंद्रित है, इसलिए भारत से होने वाले जेनेरिक दवाओं के निर्यात पर इसका असर नगण्य रहेगा।

भारत में न तो दवाओं की कमी होगी और न ही यहां के मैन्युफैक्चरर्स को कोई बड़ा वित्तीय घाटा उठाना पड़ेगा।

जेनेरिक दवाएं गुणवत्ता और प्रभाव के मामले में ब्रांडेड दवाओं के समान ही होती हैं, लेकिन उनकी कीमत काफी कम होती है।

पंजाब की आप सरकार ने दी 'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना' को मंजूरी

पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 1,000 से 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता

चंडीगढ़ ।

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना' के कार्यान्वयन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,500 रुपए वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डाली जाती है। यह कदम आम आदमी पार्टी द्वारा 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में है, जिसमें महिलाओं को मासिक भत्ता देने की बात कही गई थी। पात्रता मानदंडों के मुताबिक योजना का लाभ लेने वाली किसी परिवार की पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 2 अप्रैल की अधिसूचना के मुताबिक मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगी भी पहले से दी जा रही पेंशन के अलावा योजना के तहत पूर्ण वित्तीय लाभ पाने की हकदार होंगी। मंत्रिमंडल ने रविवार को इस योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी और अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाएंगे।

मथाभंगा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निसीथ प्रामाणिक पर 16 आपराधिक मामले लंबित

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच कूच बिहार जिले की मथाभंगा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निसीथ प्रामाणिक फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनके खिलाफ हत्या, दंगा भड़काने और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े कुल 16 आपराधिक मामले लंबित हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी करार नहीं दिया है।

चुनावी हलफनामे के अनुसार, इन मामलों में से 11 केस 2018 से 2024 के बीच दर्ज हुए हैं, जबकि बाकी 2009 से 2014 के बीच में दर्ज हुए हैं।

2020 में दर्ज मामले में उन पर जानलेवा हथियारों के साथ दंगा करने और हत्या का आरोप है।

वहीं मार्च 2024 में दर्ज एक अन्य मामले में डकैती की तैयारी और अवैध हथियार रखने के आरोप लगाए गए हैं।

हिंसा रोकने के लिए आयोग सख्त, पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगी केंद्रीय बलों की 500 कंपनियां

कोलकाता ।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव नतीजे आने के बाद भी कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 500 कंपनियां राज्य में तैनात रहेंगी। यह तैनाती आयोग के अगले आदेश तक जारी रहेगी, ताकि मतगणना के बाद संभावित राजनीतिक हिंसा को पूरी तरह से रोका जा सके। प्रत्येक कंपनी में लगभग 80 से 100 जवान शामिल होते हैं, जो राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनावी प्रक्रिया को हिंसा, डर और प्रलोभन से मुक्त रखा जाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद होने वाली हिंसा के पिछले इतिहास को देखते हुए आयोग इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई व्यापक हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे। उस समय लगभग 1,970 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिनमें हत्या, यौन उत्पीड़न और आगजनी जैसे संगीन मामले शामिल थे। निर्वाचन आयोग ने न केवल सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा चुनाव से ठीक पहले 832

सत्ताधारी दल के नेताओं को दी गई विशेष वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा करने और सुरक्षाकर्मियों का सभी दलों के बीच समान वितरण करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, सत्ताधारी दल के लिए प्रचार करने के दोषी पाए गए खंडाघोष विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त बीडीओ और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आयोग उन थोक तबादलों पर भी नजर रख रहा है, जो चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले बड़े पैमाने पर किए गए थे। इसी बीच, मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव और हंगामे के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के मुख्य साजिशकर्ता मोफक्करुल इस्लाम को सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया है।

जम्मू-कश्मीर में 120 साल पुराने ऐतिहासिक मोहरा पॉवर प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करेगा भारत

जम्मू ।

सिंधु जल संधि को लेकर कड़े रुख और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच भारत ने जम्मू-कश्मीर में एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। उत्तर कश्मीर के बारामुला जिले के उरी सेक्टर में स्थित 120 साल पुराने मोहरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। करीब तीन दशकों से बंद पड़े इस ऐतिहासिक संयंत्र को पुनर्जीवित करने का फैसला न केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1905 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने जलविद्युत संयंत्रों में से एक है, जो 1992 की भीषण बाढ़ के बाद से पूरी तरह ठप पड़ा था। अब जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस गौरवशाली विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ वापस लाने की तैयारी पूरी कर ली है। जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस प्रोजेक्ट के रेनोवेशन, अपग्रेडेशन और ऑपरेशन के लिए मंजूरी दे दी है। इस दिशा में आईआईटी रुड़की को विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपडेट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसकी टीम ने हाल ही में घाटी का दौरा कर डिजाइन संबंधी आवश्यक सुझाव दिए हैं। करीब 10.5 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना की खास बात इसका अनोखा कनाडाई डिजाइन है, जिसमें 10-11 किलोमीटर लंबी लकड़ी की नहर (फ्लूम) के जरिए पानी टर्बाइन तक पहुंचाया जाता था। हालांकि 10.5 मेगावाट की क्षमता सुनने में कम लग सकती है, लेकिन झेलम नदी पर स्थित होने के कारण इसका रणनीतिक महत्व कहीं अधिक है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत ने सिंधु जल संधि के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया है और अपनी जलविद्युत क्षमता को 2035 तक बढ़ाकर 11,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। झेलम नदी पर स्थित पुराने प्रोजेक्ट्स को सक्रिय करना और नए निर्माणों को गति देना सीधे तौर पर भारत के जल संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण और उनके अधिकतम उपयोग की दिशा में एक स्पष्ट संकेत है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की इस सक्रियता से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ना तय है, क्योंकि यह न केवल क्षेत्रीय ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करेगा बल्कि जल प्रवाह के प्रबंधन में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी स्पष्ट किया है कि सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए इन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। ऐतिहासिक मोहरा का दोबारा सक्रिय होना कश्मीर की बिजली जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक बनेगा।

सिलवासा में नाइट्रोजन गैस गोदाम में भीषण विस्फोट, तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत

स्कूल से महज 30 मीटर दूर हुआ धमाका, बड़ी त्रासदी टली; प्रशासन ने शुरू की जांच

अहमदाबाद ।

दादरा नगर हवेली के सिलवासा में आज एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शहर के डैम के पास स्थित एक नाइट्रोजन गैस गोदाम में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसपास का इलाका कांप उठा। इस हादसे में गोदाम में काम कर रहे तीन मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। गैस सिलेंडरों के टुकड़े दूर-दूर तक जाकर गिरे, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।

घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस गोदाम में विस्फोट हुआ, वह एक निजी स्कूल से मात्र 30 मीटर की दूरी पर स्थित था। हालांकि, सौभाग्य से विस्फोट की दिशा और तीव्रता स्कूल की ओर नहीं गई, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। अगर स्थिति थोड़ी भी अलग होती, तो कई मासूम बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। फिलहाल इलाके को सुरक्षित कर लिया गया है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई हैं।

प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि नाइट्रोजन गैस के रिफिलिंग या स्टोरेज में किसी तकनीकी खामी के कारण यह विस्फोट हुआ हो सकता है। प्रशासन अब यह भी जांच कर रहा है कि गोदाम के पास आवश्यक अनुमति थी या नहीं, और आखिर रिहायशी इलाके व स्कूल के इतने पास यह गोदाम कैसे संचालित हो रहा था। इस हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।